

02 सड़कों पर मौत की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा?

06 सिलिकॉन सेल: एआई मॉडल बायोमेडिसिन को बदल सकते हैं

08 ए-वन बिल्डिंग हादसा: ठेकेदार पर कार्रवाई शूच, पेटी कांटेक्टर को बनाया गया निशाना

दिल्ली का प्रशासक कौन, परिवहन आयुक्त या उपराज्यपाल दिल्ली ?

क्या दिल्ली के प्रशासक (उपराज्यपाल दिल्ली) प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में कर रहे हैं कार्य या है कुछ और ही माजरा ? संजय बाटला



दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा जिस प्रकार से कार्य और आदेश जारी किए जा रहे हैं उन्हें देख कर यह लगने लगा है की दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल दिल्ली नहीं अपितु परिवहन आयुक्त पद पर आसीन प्रशासनिक अधिकारी है।

1. दिल्ली की जनता के वाहनों को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रेप डीलरों को बिना पैसे के सौंप देना,
2. एक निजी कंपनी का कांटेक्टर खत्म होने के बावजूद उसे बार बार एक्सटेंशन देना
3. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त करना
4. राजपत्र अधिसूचना द्वारा जनहित में कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को बिना सूचना के बंद कर के अन्य कार्यालय में विलीन कर देना,

5. जनता द्वारा आनलाइन आवेदन की गलती होने पर उसके द्वारा बिना प्रयोग की फीस को जप्त कर लेना

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के दिशा निर्देशों को दरकिनारा कर दिल्ली में गैर कानूनी ढंग से एक लाख की रोक को दरकिनारा करते हुए नए वाहनों को लाने की इजाजत देना,

7. ईवाहनों को राज्य परिवहन विभाग के द्वारा प्राप्त अनुमति के बाद भी पंजीकरण ना करना,

8. उच्च न्यायालय और उपराज्यपाल के निर्देश के बाद भी दिल्ली की बंदिस सड़कों पर ई रिक्शा चलवाना,

9. निजी नंबरों के वाहनों द्वारा व्यवसायिक गतिविधि होते हुए जानने के बाद भी कार्यवाही नहीं करवाना

10. निर्भया कांड पर गृह मंत्रालय सचिव कमेटी के द्वारा आदेशित महिला सुरक्षा के कार्यों को आज तक आदेशित तरीके से लागू ना करना

11. व्यवसायिक सवारी वाहनों में कैमरे ना लगवाना

12. पुराना वाहन स्क्रेप हुए बिना नए वाहन को खरीदने की इजाजत देना

जैसे अनगिनत कार्य जो जनता को असुरक्षित और परेशान करने में सक्षम हैं के बाद भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के चुप रहने का अर्थ क्या समझे जनता, बड़ा सवाल ?

लाल किले पर हुए कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत



दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार शाम हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट शाम करीब 7 बजे एक हंडई 120 कार में हुआ।

नवदीप सिंह

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार शाम हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट शाम करीब 7 बजे एक हंडई 120 कार में हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई व कोलकाता सहित कई अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लाल बत्ती पर रुकी और उसकी गति धीमी हो गई। विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) और फॉरेंसिक विज्ञान के प्रमुखों को जांच में सहायता करने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ टीम भेजने का भी निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने विस्फोट के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव से बात की। उन्होंने बताया कि तीनों शीर्ष अधिकारियों ने गृहमंत्री को घटना के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि एनएसजी के विशेषज्ञ और एनआईए के जांच अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) लाल किले में हुए विस्फोट की जांच कर रही है।

"भारत का आटोमोबाइल क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और जीएसटी में कटौती।"

दोपहिया वाहन, ग्रामीण ही नहीं शहरी भारत की भी रीढ़ है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कमेवेशन हर घर-परिवार में होता है। इस साल अक्टूबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत कहा जा सकता है। शुभ संकेत इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में वैश्विक आर्थिक हालात बेहद अनिश्चित बने हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं विश्व अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं अवश्य ही प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि आज कई देशों में बेरोजगारी और मुद्रा अस्थिरता की स्थिति तक बनी हुई है। ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन से उत्पादन लागत बढ़ रही है। यहां तक कि निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी है। विकासशील देशों पर कर्ज और व्यापार घाटे का दबाव बढ़ रहा है। इन सबके बीच तथ्यां और संतुलित आर्थिक नीतियों की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे अनिश्चित वैश्विक आर्थिक हालात में एफ.ए.डी.ए. के दोपहिया वाहन बिक्री के आंकड़े राहत भरें हैं और ये कहीं न कहीं उपभोक्ताओं के लौटते भरोसे का भी प्रतीक है।

एफ.ए.डी.ए. के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री लगभग 31.5 लाख (3.15 मिलियन) यूनिट्स रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह वृद्धि पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में लगभग +51.76% है। 142-दिन (त्योहार अवधि) में दोपहिया वाहनों की बिक्री वर्ष-पूर्व की तुलना में +22% रही तथा इस दौरान समग्र वाहन बिक्री +21% रही। न केवल दोपहिया वाहन, बल्कि इस महीने में (अक्टूबर माह 2025 में) चौपहिया वाहनों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। एफ.ए.डी.ए. के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में कुल वाहन रिटेल 40.23 लाख यूनिट (वाहन दर साल लगभग 17.7% की वृद्धि) रही। वहीं दूसरी ओर पैसेंजर वाहन (चारपहिया) 5.57 लाख यूनिट (वाइ ओ वाइ वृद्धि लगभग 11.35%) तथा वाणिज्यिक वाहन (कमर्शियल व्हीकल्स) 1,07,841 यूनिट (वाहन दर साल लगभग 17.7% की वृद्धि) रही। दरअसल, वाहनों की बिक्री बढ़ने के पीछे कुछ कारण रहे। मसलन, सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी 2.0 सुधारों के अंतर्गत एंटी-लेवल दोपहिया वाहनों पर टैक्स दरों में कटौती हुई, जिससे



इन वाहनों की कीमतें कम हुईं और खरीदने वालों के लिए आकर्षक बनीं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि शहरी की तुलना में कहीं अधिक रही है। वास्तव में, दोपहिया वाहनों की बिक्री में ग्रामीण-शहरी वृद्धि का अंतर काफी उल्लेखनीय रहा। त्योहारों का सीजन (दशहरा-दिवाली) और ग्रामीण स्थानों में मांग में वृद्धि इसका विशेष कारण रहे। दरअसल, अच्छे मानसून एवं ग्रामीण क्रय शक्ति ने भी इसमें काफी मदद की। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूँ कि एफ.ए.डी.ए. का पूरा नाम है-

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन)। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन (नेशनल बाडी) है, जो भारत में सभी वाहन डीलरों (आटोमोबाइल डीलर्स) - जैसे कि कार, बाइक, ट्रक, बस आदि के शोरूम या बिक्री केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में, यह भारत के वाहन डीलरों का एक प्रतिनिधित्व संगठन है। जो सरकार, कंपनियों और ग्राहकों के बीच एक संतुलनकारी भूमिका निभाता है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूँ कि वाहनों की बिक्री (दोपहिया, चौपहिया) से किसी भी अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होता है। दरअसल, वाहन उद्योग (दोपहिया और चौपहिया) को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इससे न केवल परिवहन सुगम होता है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है - जैसे कि उत्पादन, बिक्री, मरम्मत, बीमा, और परिवहन सेवाओं में। वाहन उद्योग में वृद्धि से स्टील, पेट्रोलियम, रबर, प्लास्टिक, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सहायक उद्योगों को भी गति मिलती है। इतना ही नहीं, सरकार को वाहन बिक्री पर लगने वाले टैक्स, जीएसटी, और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में भारी राजस्व प्राप्त होता है। वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यटन, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी तेजी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों के प्रसार से किसानों और छोटे व्यवसायियों की उत्पादकता बढ़ती है। आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन हमारे देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। इस तरह वाहन उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति-तीनों का प्रमुख आधार बन चुका है। बहरहाल, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के आंकड़े यह बताते हैं कि अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में 11.35 और

अच्छा रहा। उत्पादन अच्छा होने से किसान समृद्ध और खुशहाल हुए हैं और उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ा है, आमजन के हाथ में पैसा आया है और शायद यही वजह भी है कि आज उपभोक्ता मांग में भी सुधार देखा जा रहा है। आज किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। यह सकारात्मक परिवर्तन न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कहीं न कहीं उत्साहजनक व सकारात्मक संकेत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खरी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। वर्ष 2026-27 के खरी विपणन सत्र के लिए घोषित नए एमएसपी के अनुसार, गेहूँ का मूल्य ₹ 2,585 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष ₹ 2,425 था - यानी ₹ 160 प्रति क्विंटल की वृद्धि। इसी तरह जौ की एमएसपी ₹ 2,150 (₹ 170 की वृद्धि), चना ₹ 5,875 (₹ 225 की वृद्धि), मसूर ₹ 7,000 (₹ 300 की वृद्धि), सरसों ₹ 6,200 (₹ 250 की वृद्धि) और कुसुम ₹ 6,540 (₹ 600 की वृद्धि) प्रति क्विंटल तय की गई है। दरअसल, सरकार का यह लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल की लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य मिले ताकि उन्हें उचित लाभ प्राप्त हो सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक में एमएसपी के तहत अनाजों की सरकारी खरीद में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, इसी अवधि में किसानों को एमएसपी के तहत भुगतान की राशि लगभग तीन गुना बढ़कर ₹ 3.33 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में निवेश को भी नई गति मिली है। अतः कुल मिलाकर यहां यह बात कही जा सकती है कि एमएसपी में वृद्धि, अनुकूल मौसम (अच्छा मानसून) और विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों के चलते आज भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक

गतिविधियाँ लगातार तेज हो रही हैं, जिसका सकारात्मक असर खुदरा बाजारों और औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखाई पड़ा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में ऑटो क्षेत्र का भविष्य तेजी से बदलते परिवेश में पर्यावरणीय संतुलन के साथ जुड़ा जा रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड टैक्नोलॉजी और ग्रीन फ्यूल जैसे इन्वेंशन, सीएनजी और हाइड्रोजन पर आधारित वाहनों का विस्तार हो रहा है। सरकार भी 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन' और 'फेम इंडिया स्कीम' जैसी योजनाओं से इस दिशा में प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले वर्षों में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल वाहनों का बोलबाला होगा। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि देश की तेल आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ऑटो उद्योग में तकनीकी नवाचार, बैटरी निर्माण, रीसाइक्लिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर करेगा। इस प्रकार, भारत का ऑटो क्षेत्र भविष्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि फिलहाल, सरकार को यह चाहिए कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा आकर्षक पहल करे, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल वाहनों की बजाय ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित हों। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन हर शहर और हाइवे पर तेजी से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को चार्जिंग की दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, सरकार को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रेप नीति को भी सखी से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि सड़क पर सिर्फ सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल वाहन ही चलें। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि ऑटो सेक्टर में नई तकनीक और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब ये सारी नीतियां प्रभावी रूप से लागू होंगी, तब वाहनों की बिक्री और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। निश्चित ही इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। लोग भी स्वच्छ और सस्ती यात्रा का आनंद ले पाएंगे। ऊर्जा की भी बचत होगी और तेल आयात पर निर्भरता घटेगी। उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और हरित विकास को बल मिलेगा। इस तरह देश का ऑटो क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों ही तेजी से आगे बढ़ेंगे।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

पिकी कुंडू महासचिव

म्यांमार में KK पार्क के 150 साइबर ठिकानों का विध्वंस—चीन-प्रायोजित साइबर अपराध नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

म्यांमार द्वारा KK पार्क में 150 से अधिक स्कैम बिल्डिंग्स को गिराना दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय चीन-समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। इससे उनकी संरचना बिखर गई है, ऑपरेटिव्स भाग गए, और क्षेत्रीय स्तर पर ट्रांसनेशनल फ्रॉड के खिलाफ प्रतिरोध का संकेत गया है।

क्या हुआ: KK पार्क स्कैम परिसर पर कार्रवाई

म्यांमार की सैन्य सरकार ने म्यावाडी टाउनशिप के थाई सीमा के पास स्थित KK पार्क में 148 इमारतों को गिराने की घोषणा की।

इनमें डार्मिंटो, चार मंजिला अस्पताल, जिम, स्पा और कराओके पार्लर जैसी लक्जरी सुविधाएं शामिल थीं—जो स्कैम वर्कर्स को रखने और ट्रांसनेशनल फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल होती थीं।

अब तक 101 इमारतें गिराई जा चुकी हैं, 47 पर काम जारी है।

गैर परिसर पहले 2,000 से अधिक स्कैमर्स का अड्डा था, जिनमें से कई छापा के दौरान थाईलैंड भाग गए।

KK पार्क क्यों था अहम: चीन-लिंकड फ्रॉड का नर्व सेंटर

आज का साइबर सुरक्षा विचार

स्कैम चलाने को मजबूर किया जाता था।

चीन-समर्थित स्कैम इकोसिस्टम पर प्रभाव

1. भौतिक ढांचे का विघटन
 - 0 सुरक्षित अड्डों और लक्जरी परिसरों की समाप्ति से स्कैम लॉजिस्टिक्स और मनोबल कमजोर हुआ।
2. ऑपरेटिव्स को स्थान बदलना पड़ा, जिससे गिरफ्तारी का खतरा बढ़ा।
3. इंटेलिजेंस की प्राप्ति
 - 0 छापा में मिले डिवाइस, दस्तावेज रूट्स शामिल थे।
 - 0 वर्कर्स को अक्सर तस्करी या हाई पे के झूठे वादों से लुभाया जाता था, फिर गिरगारी में

0 ट्रांसनेशनल फ्रॉड नेटवर्क और उनके वित्तीय प्रवाह को मैप करने में मदद मिलेगी।

3. चीन पर क्षेत्रीय दबाव

0 म्यांमार की कार्रवाई—भले ही अंतरराष्ट्रीय दबाव में हो—ASEAN देशों में चीन-समर्थित डिजिटल अपराध के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध का संकेत है।

0 थैलीलैंड, लाओस और कंबोडिया भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।

4. भारत की साइबर डिप्लोमेसी को बढ़ावा

0 भारत ने हाल ही में म्यांमार के स्कैम सेंटर्स से तस्करी किए गए 270 नागरिकों को वापस लाया।

0 ऐसे क्रेकडाउन भारत के लिए साइबरक्राइम सिंधियों, इंटेलिजेंस साझेदारी और प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल की मांग को मजबूत करते हैं।

यह एक निर्णायक मोड़ है। KK पार्क का गिरना सिर्फ एक विध्वंस नहीं—बल्कि एक घोषणा है कि डिजिटल अपराध सिंडिकेट्स, चाहे जितने भी फंडेड या राज्य-समर्थित हों, समन्वित कार्रवाई से कमजोर किए जा सकते हैं। भारत को इस मोमेंटम का लाभ उठाकर नागरिकों को संरक्षित रखना चाहिए।

https://tolwa.com/about.html
tolwadelhi@gmail.com
tolwaindia@gmail.com

दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी तक पहुंचा, अगले कुछ दिन नहीं मिलेगी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की हवा में सोमवार को प्रदूषण का स्तर मानकों से पांच गुना तक ज्यादा दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं आसपास के इलाकों में भी हवा में प्रदूषण का स्तर 300 एक्वआई से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। सेटलाइट से प्राप्त तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि सीमा से लगे पाकिस्तान के कई हिस्सों और पंजाब-हरियाणा में किसान बड़े पैमाने पर पाराली जलाई जा रही है। यहां से निकले धुएँ की चादर दिल्ली और एनसीआर के चारों ओर देखी जा सकती है। हवा की बेहद धीमी गति के चलते ये धुआँ हवा में फंसा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को इस दमघोड़ हवा में ही सांस लेना होगा।

दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सोमवार शाम हवा में पीएम 10 का स्तर 532 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। वहीं यहां हवा में पीएम 2.5 का स्तर 326 माइक्रोग्राम के करीब दर्ज किया गया। इसी तरह रोहिणी इलाके में पीएम 10 का स्तर 610 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। जबकि पीएम 2.5 का स्तर 381 माइक्रोग्राम के करीब दर्ज किया गया। मथुरा रोड, आईटीओ, मंदिर मार्ग सहित कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर मानकों से कई गुना दर्ज किया गया। मानकों के तहत हवा में पीएम 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से पांच गुना हुआ

जहरीले धुएँ में सिर्फ दिल्ली या एनसीआर के लोगों को ही सांस नहीं लेनी पड़ रही है। आसपास के शहरों पर भी इसका असर है। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट संस्था में लम्बे समय से वायु प्रदूषण पर काम कर रहे विवेक चटोपाध्याय कहते हैं कि पाराली के धुएँ और प्रदूषण के चलते दिल्ली ही नहीं आसपास के लगभग 250 किलोमीटर के इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। पूर्वानुमान बता रहे हैं ऐसा अभी कुछ दिन और रहेगा। दिल्ली और एनसीआर के आसपास कई शहर ऐसे हैं जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक 300 के स्तर को पार कर गया है। ऐसा लगता है कि यह एक साथ हुआ है, इसलिए सामूहिक तौर पर बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषित धुएँ को इस चादर में हरियाणा के छह शहरों, उत्तर प्रदेश के सात शहरों और पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। आसपास के कुछ और शहरों में भी हालात की चिन्ता नहीं है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

नवजात शिशु का पहला वर्ष, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा होना चाहिये...?

जन्म से एक साल तक के बच्चों की देखभाल कैसे करे इस पर काफी सवाल आये...

हम चाहते तो अलग अलग भी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन एक ही जगह बच्चे के पालन पोषण की जानकारी देना सही लगा इसलिए पोस्ट कुछ लम्बी हो गयी है।

लेकिन उम्मीद करते हैं नये माता और पिताओं के लिये काफी यूजफुल होंगी...

आइये जानते हैं कुछ टिप्स जो आपको हैल्प करेगी....

बच्चे का वजन जन्म के बाद 10% घटता है... नवजात शिशु जन्म के कुछ दिनों के अंदर अपना 10% वजन खोता है।

यह साधारण बात है और यह सभी बच्चों के साथ होता है।

लेकिन नवजात शिशु जन्म से 14 दिनों के अंदर अपने जन्म के समय (birth weight) के वजन को वापस पा लेता है।

आगले 4 से 6 महीने में शिशु का वजन, अपने जन्म के वजन (birth weight) का दुगुना हो जाता है।

जन्म के समय वजन जरूर करायें बेबी का... फिर एक साल तक प्रति सप्ताह वजन करायें और ये सुनिश्चित करें कि बेबी का वजन प्रति सप्ताह बढ़े, फिर चाहे वो 100 ग्राम ही क्यों न बढ़े।

इसके लिये जरूरी है कि हमेशा एक ही वेट मशीन और एक ही बेबी कपड़े यूज करें क्योंकि कपड़े का वजन भी रिजल्ट गलत दे सकता है....

एक साल का होते होते शिशु अपने जन्म के वजन (birth weight) का तीन गुना हो जाता है।

दूसरे साल में, बच्चे का वजन 2 से 3 किलो ही बढ़ता है इससे ज्यादा बढ़े तो अच्छा है लेकिन इससे कम हो तो चिंता की बात है।

कैसे जाने आपके बेबी का पेट भर रहा है... अगर आप के बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है तो वो दिन में कम से कम 6 से 8 बार अपना डायपर गिला करा रहा है तथा उसे दिन में कई बार पॉटी तो यह इस बात को दर्शाता है कि बच्चे का विकास ठीक तरह से हो रहा है।

बच्चा खुश है अच्छी नींद ले रहा है तो भले ही उसके गाल गोले मूला टाइप नहीं है। आप खुश रहें, आपका बेबी स्वस्थ है।

जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसे पॉटी कम होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसे पॉटी तीन दिनों में एक बार हो। यह बिलकुल नॉर्मल सी बात है।

नोट: 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए !

तो कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चे का वजन क्योंकि ये एक खास समस्या है नई माँओं के लिये।

लेकिन इसका जवाब भी यही है... सही ढंग से फीडिंग नही करा पाना ही कारण है बच्चे का वजन नही बढ़ने का....

आइये समझते हैं बेस्ट तरीका फीडिंग का, जिससे मिल्क के सभी न्यूट्रिशन बच्चे को मिले...

एक उदाहरण देते हैं आपको... अगर आपने नहाना है तो गीजर आन किया, तो पहले ठंडा पानी आयेगा, फिर गुनगुना, फिर गर्म।

यही बात फीडिंग समय की है, पहले मिल्क आता है, पतला होगा, फिर कुछ गाढ़ा उसके बाद आता है, फेट वाला मिल्क जो कि बच्चे का वजन बढ़ाने के काम आता है।

यदि बेबी इस मिल्क तक नही पहुंच पाता है तो उसका पेट तो भरगा ही, साथ में विकास भी होगा, लेकिन मटर मिल्क का फेट है वो नही मिलेगा इसी कारण अक्सर फीडिंग के बाद भी मटर घंट कम नही तो पता चला दूध नही आयेगा।

बेबी को कम से कम 10 से 15 मिनट फीड करायें, वैसे समय बच्चे के लैच करने पर भी डिपेंड करता है। दूसरी जरूरी बात कि हर 2 घण्टे में फीड कराती रहें।

सही उदाहरण यदि आपने गीजर से पानी लिया और कुछ समय बाद आन करो तो ठंडा पानी नही आयेगा। ऐसे ही यदि जल्दी जल्दी स्तनपान करायेंगी तो पतला दूध नही आयेगा।

बेबी को अच्छा मिल्क मिलेगा, बेबी को रात में भी बराबर स्तनपान करायें।

तीसरी जरूरी बात बेबी को सभी पोषक तत्व मां के दूध से मिलेगी तो जरूरी है, नवप्रसूता मां के आहार मे दूध मेवा दाले फल जूस हरी सब्जी शामिल हो

अभी जाने, 6 महीने से बड़े बच्चे को क्या दें ? अगर आप का शिशु छह महीने से बड़ा है तो आप को अपने शिशु को दिन में तीन बार देना चाहिए। इसके साथ साथ दिन में कम से कम दो बार स्तनपान भी करना चाहिए।

जब तक कि आपका शिशु एक साल का ना हो जाये आप उसे ठोस आहारों के साथ साथ स्तनपान भी कराती रहें।

शिशु का वजन बढ़ाने वाले आहार चिलिये अब बात करते हैं उन साधारण से दिखने वाले कचमकरी आहारों के बारे में जो आश्चर्यजनक रूप से आप के बच्चे का वजन बढ़ने की छमता रखते हैं।

अब जब आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो आप उसे नीचे दिए आहार खिला सकती हैं।

सुनने में ये बहुत ही साधारण आहार लगेंगे लेकिन बच्चों का जवान बढ़ाने की इनमें विलक्षण ताकत है।

1. केला है उर्जा का अद्भुत स्रोत

केला प्राकृतिक उर्जा का अद्भुत स्रोत है। केवल एक केले से बच्चे को 100 कैलोरी से ज्यादा उर्जा मिलता है।

केले में कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, डाइट फाइबर, विटामिन-C और B6 भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।

केला उन आहारों में से एक है जो शरीर को तुरंत उर्जा प्रदान करने में सक्षम है।

यह बहुत आसानी से पच भी जाता है।

पूरे भारत में आप कहीं भी जाइये, केला एक ऐसा फल है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे शिशु के लिए आहार बनाना भी बहुत आसान है। यही वजह है कि सफर के दौरान बच्चों के लिए केला सर्वोत्तम आहार है।

केला है उर्जा का अद्भुत स्रोत... केले को आप बहुत आसानी से कहीं भी ले भी जा सकती हैं।

बस दो केला लीजिये, रुमाल में लपेटिये, अपने परस में रखिये, और कई घंटे के लिए अपने शिशु के आहार को लेकर निश्चित हो जाइये।

ना अलग से टिफिन डब्बा लेने की आवश्यकता और ना ही ये सोचने की, कि बच्चे को आहार कहीं और किस तरह खिलाया जाये।

अपने शिशु को आप केला कई तरह से खिला सकते हैं।

जैसे कि आप केले की स्मूदी (smoothies), (shakes), केक (cakes) या पुडिंग (puddings) बना के शिशु को दे सकती हैं। और अगर आप को कुछ भी ना समझ आये तो बस केले को छील कर बच्चे को खाने के लिए दे सकती हैं।

2. गाय का शुद्ध देशी घी गाय के शुद्ध देशी घी में पोषण बहुत ही उच्च मात्रा में होता है। इसीलिए शिशु का वजन बढ़ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आहार है।

गाय का शुद्ध देशी घी जैसे ही आपका शिशु आठ महीने (8 months) का होता है आप उसे देशी घी दे सकती हैं। शिशु को देशी घी देने के लिए उसके आहार में देशी घी के कुछ बूंद डाल सकती हैं। जैसे कि उसके खिचड़ी में या राटी में लगा के।

जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा आप देशी घी की मात्रा बढ़ा सकती हैं।

गाय के शुद्ध देशी घी में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसी लिए बच्चे को देशी घी बहुत ही सीमित मात्रा में दें।

3. सेहत से भरपूर रागी रागी बहुत ही पोषक और स्वास्थ्यवर्धक है। बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए तो ये बेहतरीन आहार है। इससे बच्चे को प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, B2, और दुसरे बहुत से मिनिरल (खनिज) मिलते हैं जो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है।

सेहत से भरपूर रागी... बच्चे रागी को बहुत आसानी से पचा लेते हैं। शिशु का वजन बढ़ने के लिए आप शिशु के बदन में रागी का इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे रागी का हलवा बड़े चाव से खाते हैं। इसके आलावा आप बच्चे को रागी का खिचड़ी भी बना के खिला सकती हैं।

4. वजन बढ़ाये दही दही में दूध का वासा और पोषक तत्व होता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाये तो बच्चों में दूध की तुलना में दही ज्यादा आसानी से पचा जाता है।

दही शिशु को उसके विकास के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व सही अनुपात में पहुंचता है। इससे शिशु को भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन-स और मिनरल्स मिलता है।

वजन बढ़ाये दही। दही शिशु का रोग प्रतिरोधक छमता भी बढ़ता है और अगर बच्चे को दस्त की समस्या है तो उससे भी आराम दिलाता है।

शिशु रोग विशेषज्ञ इस बात की राय देते हैं कि जब बच्चा 7 महीने या 8 महीने का हो जाये तब आप उसे दही देना शुरू करें।

शिशु दूध में उपलब्ध प्रोटीन को बहुत आसानी से हजम नहीं कर सकता है। लेकिन दही बनने के दौरान, फर्मेन्टेशन प्रक्रिया में दूध का प्रोटीन इस तरह से टूटता है जिसे की बच्चे का पाचन तंत्र आसानी से पचा लेते हैं।

आप दही से शिशु के लिए कई तरह के आहार बना सकती हैं, जैसे कि राइस curd rice, स्मूदी smoothies, छाँछ buttermilk या फ्रूट प्लेवर्ड कई fruit-flavored curd (दही)।

5. ओट्स (Oats) रखे पाचन तंत्र को दुरुस्त ओट्स में फाइबर भरपूर से होता है। इस वजह से यह शिशु को कब्ज नहीं होने देता है और उसके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। ओट्स में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है।

साथ ही यह आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, थिआमिन (thiamine) और फॉस्फोरस का भी बेहतरीन स्रोत है।

ये सभी खनिज बच्चे के विकास में तो योगदान देते ही हैं, साथ ही वजन का सही अनुपात भी बनाये रखने में मदद करते हैं।

ओट्स (Oats) रखे पाचन तंत्र को दुरुस्त। ओट्स को बेबी फूड की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को ओट्स उसके आहार में कई तरह से दे सकती हैं।

जैसे कि आप अपने बच्चे को ओट्स का डोसा, खीर, खिचड़ी, कुकीज (cookies) या बस दूध में मिला के भी खिला सकती हैं।

6. आलू दे तंदरुस्ती आलू वो आहार है जो आप अपने बच्चे को ठोस आहार शुरू करते हैं पहले दिन से खिलाना शुरू कर सकती हैं। इसमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। सरल भाषा में स्टार्च को आप कार्बोहाइड्रेट कह सकती हैं। इससे शिशु को उर्जा मिलता है।

बच्चे बहुत चंचल होते हैं। दौड़ना, भागना और खेल कूद के लिए बच्चे को ढेरों उर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये उर्जा शिशु को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है।

कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ आलू में अच्छी मात्रा में विटामिन-C और B-6 और अनेक प्रकार के मिनिरल्स जैसे की फॉस्फोरस, मैग्नीसियम होता है।

आलू से शिशु आहार बनाना बहुत आसान है। आप जो भी आहार शिशु के लिए बना रही हैं, जैसे की खिचड़ी, दाल या सब्जी, आप उसमें आलू छील के डाल सकती हैं।

आप चाहें तो अपने शिशु को आलू उबल कर के



उसका चोखा बना के भी शिशु को दे सकती हैं। इसमें आप स्वाद के लिए देशी घी के कुछ बूंद भी मिला सकती हैं।

आलू बच्चों को बहुत आसानी से पच जाता है। इससे बच्चों को एलर्जी होने की भी बहुत कम सम्भावना है।

यह बच्चों का पसंदीदा आहार में से एक है। बच्चे आलू को बहुत पसंद से खाते हैं।

7. शक्करकंद आलू की ही तरह शक्करकंद को भी आप शिशु को ठोस आहार शुरू करते ही दे सकती हैं।

यह बहुत ही पोषक आहार है और बच्चों को आसानी से पच जाता है। आप इसे उबल कर और आलू की तरह मैश कर के बच्चे को खिला सकती हैं।

शक्करकंद (Sweet Potatoes) पोषक तत्वों का भंडार है। इससे बच्चे को विटामिन-A (जिसे बीटा केरोटीन भी कहते हैं), विटामिन-C, कॉपर, मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन-B6 मिलता है।

इसके आलावा बच्चे को डायटरी फाइबर भी मिलता है।

8. दाल बनाये मांस पेशियाँ (Muscles) दाल में बहुत कैलोरी होती है, जिस वजह से यह बच्चे का वजन बढ़ाने में बहुत सहायक है।

अगर आप का बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो आप अपने बच्चे को मूंग दाल का सूप बना के दे सकती हैं।

आप चाहें तो बच्चे को दाल का पानी भी दे सकती हैं।

मूंग का दाल और उरद का दाल बच्चों को बहुत आसानी से पच जाता है। इसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, साथ ही इससे शिशु को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मिलता है। दाल में वसा की मात्रा बहुत कम होती है और फाइबर बहुत होता है।

दाल बच्चों को बहुत तरीके से दिया जा सकता है। आप बच्चों को दाल की खिचड़ी, दाल का सूप या दाल का हलवा बना के दे सकती हैं।

शिशु आहार तयार करने के लिए आप स्वाद का तड़का, घुप की रसियाँ में देख सकती हैं।

9. अवोकाडो (Avocado) स्वस्थ वासा से युक्त अवोकेडो में दो चीज भरपूर मात्रा में है - स्वस्थ वासा और फाइबर।

इसके साथ यह बच्चे महत्वपूर्ण एससियल मिनरल्स और विटामिन्स भी प्रदान करता है। आप शिशु को छेह महीने होते ही अवोकेडो दे सकती हैं।

अवोकेडो को कई तरह से बच्चों को दिया जा सकता है। शुरुआत में आप अवोकेडो को पीस के (प्यूरी) या आलू के चोखे की तरह मैश कर के खिला सकती हैं।

इसके आलावा आप अगर आप बच्चों के लिए शोक, स्मूदी या डिजर्ट बना रही हैं, तो आप उसमें अवोकेडो मिला सकती हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से आइस क्रोम मिलाया जाता है।

10. खिचड़ी तो बढ़ाये शिशु का वजन शिशु में ठोस आहार शुरू करते वक्त खिचड़ी उन आहारों में से एक है जो शिशु को सबसे पहले दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 महीने के बच्चे का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है।

लेकिन खिचड़ी इतना सरल है कि इसे पचाने के लिए शिशु के पाचन तंत्र पे कोई बल नहीं पड़ता है। यह 6 महीने के शिशु में भी आसानी से पच जाता है।

खिचड़ी में चावल और दाल के साथ साथ आधा चम्मच गाए का शुद्ध देशी घी भी डाल देने से शिशु-आहार का ना केवल जायका बढ़ता है बल्कि यह एक ऐसा आहार में तब्दील हो जाता है जो शिशु के वजन को बहुत ही कम समय में बढ़ाने की छमता रखता है।

सबसे अच्छी बात ये है की इस आहार को शिशु बहुत चाव से खाते हैं।

11. बटर - मक्खन बटर या मक्खन शिशु के शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिशु के दिमागी विकास के लिए तो स्वस्थ-वसा तो सबसे जरूरी है।

मक्खन वसा का सबसे घनिष्ट स्रोत है। सच बात तो ये है की मक्खन शिशु को वो सारे प्रकार के वसा को प्रदान करता है जो उसके तेज शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे कि cholesterol, Vitamin A और essential fatty acids - जो ही, - कोलेस्ट्रॉल भी शिशु के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

एक उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल हानिकारक हो सकता है, लेकिन बच्चों के विकास के लिए तो ये बहुत जरूरी है।

बस एक बात का ध्यान रहे कि शिशु को जरूरत से ज्यादा मक्खन ना मिले।

शिशु का स्वस्थ विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्याधिक मोटा होना भी ठीक नहीं है। यूँकहें कि मोटा होना अनेक बीमारियों की जड़ है।

बस एक चाय की चमच भर मक्खन हर दिन शिशु के विकास के लिए बहुत है।

आप अपने शिशु को मक्खन उसके आहार में जैसे कि खिचड़ी, दाल, सूजी का हलुआ या सूप में मिला के

खिला सकती हैं।

12. पूरा गेहूँ - Whole Wheat पूरा गेहूँ यानी की बिना चलनी से छाना हुआ गेहूँ। इस गेहूँ में (Whole Wheat) में चोकर होता है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है और जिसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है।

अगर हम पूरे गेहूँ (Whole Wheat) में पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें फाइबर के साथ साथ प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, आयरन, और मैग्नीशियम होता है।

ये सभी तत्व ऐसे हैं जो शरीर को जरूरत पड़ता है शिशु का वजन बढ़ने के लिए।

गेहूँ से शिशु का वजन तो तुरंत नहीं बढ़ेगा लेकिन यह एक बहुत ही स्वस्थ तरीका है शिशु का वजन बढ़ाने के लिए।

शिशु जब दस महीने (10 months) का हो जाये तभी उसे गेहूँ से बने आहार दें। ऐसा इस लिए क्योंकि कुछ बच्चों में गेहूँ के प्रति अलर्जी होने की सम्भावना रहती जो बढ़ते उम्र के साथ कम होती जाती है।

शिशु को गेहूँ से बने आहार देते समय आहार के तीन दिवसीय नियम का पालन अवश्य करें। गेहूँ से बने आहार के उम्र के बाद अगर आप को शिशु में कोई भी एलर्जी के लक्षण दिखें तो तुरंत बिना समय गंवाये डॉक्टर की राय लें।

13. फलों का जूस.. अक्सर आप न पढ़ा होगा विशेषज्ञ इस बात पे जोर देते हैं की फलों के रस की बजाये, उनका स्मूदी (smoothie) बना के पीना चाहिए। इससे मोटापा कम होता है।

लेकिन जब बच्चे का वजन बढ़ाना हो तो फलों जूस एक बहुत अच्छा विकल्प भी है। फलों के जूस में कैलोरी की कोई कमी नहीं होती है। इसमें पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं जैसे की विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर।

यह उन माँ-बाप के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है जिनके बच्चे फलों को खाना पसंद नहीं करते हैं।

आप बच्चों के लिए घर पे ही फलों का जूस बना सकते हैं। फलों का जूस बनाने के लिए आप संतरे, आनर, अनानास का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

आप इन सबके अलग अलग जूस बना के अपने बच्चे को पिला सकती है या सबको मिला के भी जूस बना के बच्चे को पीला सकती हैं।

बच्चों के लिए जूस बनाते वक्त आप को अलग से उसमें चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है।

आप जूस का स्वाद नियंत्रित करने के लिए फलों के अनुपात में बदलाव कर सकती हैं जैसे की संतरे और आनर का मिश्रण।

गाय का दूध है शक्ति से भरपूर.. एक साल से बड़े बच्चों को गाय का दूध दिया जा सकता है।

गाय का दूध बच्चों का वजन चमत्कारी रूप से बढ़ाने की छमता रखता है।

तभी तो 20 किलो का बछड़ा, छह महीने में 100 किलो का हो जाता है।

इससे बच्चे को वो सबकुछ मिलता है जो वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है।

जैसे कि कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए, प्रोटीन मांस पेशियाँ के विकास के लिए, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स शिशु के सर्वोन्मुखी डेवलपमेंट के लिए।

एक साल से बड़े बच्चों को हर दिन कम से कम दो गिलास दूध देना चाहिए।

अगर आप के बच्चे को सादा दूध पसंद नहीं है तो आप उसे कई तरीकों से परोस सकती हैं। उदाहरण के लिए आप बच्चे को दूध का शेक बना के दे सकती हैं, जैसे कि चॉकलेट शेक, फ्रूट शेक इत्यादि।

16. पनीर है बढ़िया ! पनीर इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें गाए के दूध के सभी गुण विद्यमान हैं।

जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12 और फॉस्फोरस।

जब शिशु आठ महीने (8 months) का हो जाये तो आप तभी से उसे पनीर दे सकती हैं। अगर दूध, बच्चे को एक साल के बाद ही दें और दें भी तो सिर्फ गाय का दूध।

यह एक बेहतरीन आहार विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे को पनीर छोटे-छोटे टुकड़े में काट के भी दे सकती हैं, Finger Food की तरह। इससे बच्चे के खाने के आदत का भी विकास होगा।

पनीर उन बच्चों को भी दिया जा सकता है जिन बच्चों को गाए के दूध से एलर्जी है। लेकिन फिर भी बच्चे को पहली बार पनीर देते समय आहार के तीन दिवसीय नियम का पालन अवश्य करें। पनीर देने के बाद अगर शिशु में किसी भी एलर्जी के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

17. जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून के तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता है।

जैतून का तेल (Virgin Olive oil) जैतून का तेल में सही अनुपात में good fatty acids भया जाता है जो शिशु का वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसमें अत्याधिक मात्रा में antioxidants और phytonutrients भी मिलता

सड़कों पर मौत की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा ?

भारत में प्रतिदिन लगभग चार सौ लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। मुख्य कारण हैं — खराब सड़क डिजाइन, कमजोर प्रवर्तन, चालक प्रशिक्षण की कमी और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का अभाव। समाधान के रूप में वैज्ञानिक सड़क निर्माण, पारदर्शी लाइसेंसिंग, वाहन सुरक्षा तकनीक, पैदल यात्री अवसररचना और राष्ट्रीय दुर्घटना प्रतिक्रिया जाल की स्थापना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसे निवारक सार्वजनिक नीति बनाकर ही “शून्य मृत्यु गलियारा” का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

- डॉ प्रियंका सौरभ

भारत की सड़कों पर हर दिन लगभग चार सौ लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आँकड़ा किसी आपदा या महामारी से नहीं, बल्कि हमारी सड़कों पर व्याप्त अव्यवस्था और लापरवाही से जुड़ा है। अनेक योजनाएँ, अभियान और कानून बनने के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले देशों में गिना जाता है। सवाल यह नहीं कि सरकार ने कुछ किया या नहीं, बल्कि यह है कि हमने सड़क सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक असफलता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक संस्कृति की भी परीक्षा है।

भारत में सड़क सुरक्षा पर चर्चा अक्सर किसी बड़ी दुर्घटना या प्रसिद्ध व्यक्ति के हादसे के बाद तेज होती है, लेकिन कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनती हैं, वे अधिकतर कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत विश्व की कुल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का लगभग ग्यारह प्रतिशत अकेले वहन करता है, जबकि हमारे पास विश्व की कुल गाड़ियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। यह असंतुलन किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र के लिए चेतावनी है।

सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई गहरे और परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है — अवसररचना की गुणवत्ता और डिजाइन में गंभीर खामियाँ। हमारे अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संकेतक, डिवाइडर, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा अवरोधक नहीं हैं। कई बार सड़कों का चौड़ीकरण बिना यातायात प्रवाह के वैज्ञानिक अध्ययन के किया जाता है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सड़कें वर्षों में टूट जाती हैं और वर्षों तक बिना मरम्मत के उपयोग में रहती हैं। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता

के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

दूसरा बड़ा कारण है — कमजोर प्रवर्तन प्रणाली। भारत में यातायात नियम तो हैं, पर उनके पालन की संस्कृति नहीं है। तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के यात्रा करना और नशे की हालत में गाड़ी चलाना आम बात है। पुलिस बलों के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही तकनीकी प्रशिक्षण कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करा सकें। “ई-चालान” जैसी पहलें केवल बड़े शहरों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यातायात नियंत्रण लगभग नाममात्र का है।

तीसरा कारण है — ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था की खामियाँ। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कौशल का नहीं, बल्कि प्रक्रिया की औपचारिकता का प्रतीक बन गया है। प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण बिना समुचित परीक्षण के लाइसेंस जारी दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप असुरक्षित चालक सड़कों पर उतर जाते हैं। कई देशों में वाहन चलाना एक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है, जबकि भारत में यह केवल एक अधिकार की तरह देखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, वाहनों की तकनीकी सुरक्षा प्रणाली का अभाव भी दुर्घटनाओं में मृत्यु का बड़ा कारण है। अधिकांश वाहनों, विशेषकर ट्रक, बस और ऑटो श्रेणी में टक्कर-चेतावनी प्रणाली, एयरबैग, या ऊर्जा-अवशोषक ढाँचा नहीं होता। विकसित देशों में वाहन निर्माण के समय सुरक्षा प्रबंधन अनिवार्य है, परंतु भारत में ये केवल महंगे मॉडलों तक सीमित रहते हैं। वाहन उद्योग और नियामक संस्थाओं के बीच जवाबदेही का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

दुर्घटना के बाद की स्थिति और भी भयावह है। ट्रॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा



व्यवस्था की कमी के कारण घायल व्यक्ति समय पर उपचार नहीं पा पाते। “स्वर्णिम घंटा” यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जीवन बचाने के लिए निर्णायक होता है, परंतु हमारे देश में यह घंटा अक्सर सड़कों पर तड़पते हुए बीत जाता है। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सेवाएँ भी सीमित हैं, और जो हैं, वे ईंधन या स्टॉफ की कमी से प्रभावित रहती हैं।

सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक पक्ष भी गंभीर है। नीति आयोग के अनुसार, भारत हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग तीन प्रतिशत तक खो देता है। यानी न केवल लोग मर रहे हैं, बल्कि विकास की रफ्तार भी घट रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी क्षति है। यह केवल आँकड़ों की बात नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के सम्मान का प्रश्न है।

अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति को बदला कैसे

जाए? सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा को प्रतिक्रियात्मक नहीं, निवारक नीति के रूप में अपनाना होगा। इसका अर्थ है कि दुर्घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो दुर्घटनाओं को रोके। इसके लिए सड़क निर्माण, वाहन प्रौद्योगिकी, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।

पहला कदम होना चाहिए — वैज्ञानिक सड़क डिजाइन और रखरखाव। हर सड़क परियोजना में निर्माण से पहले “सड़क सुरक्षा लेखा-परीक्षण” अनिवार्य किया जाना चाहिए। सड़कें केवल चौड़ी नहीं, बल्कि सुरक्षित और समझदार हों। संकेतक, गति अवरोधक, क्रैश बैरियर और रात्रि प्रकाश जैसे तत्वों को डिजाइन का अभिन्न भाग बनाना होगा। उदाहरण के लिए, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में “शून्य मृत्यु गलियारा” (Zero Fatality Corridor) योजना के तहत मृत्यु

दर में पचास प्रतिशत तक कमी आई है।

दूसरा कदम, लाइसेंस व्यवस्था में सुधार। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह “लाइसेंस सेवा केंद्र” बनाकर पारदर्शी, डिजिटल और कौशल आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक चालक को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना अनिवार्य किया जाए। इससे भ्रष्टाचार घटेगा और योग्य चालक सड़कों पर उतरेंगे।

तीसरा कदम, वाहनों में सुरक्षा प्रौद्योगिकी का प्रसार। सरकार को सभी वाहनों में एयरबैग, सेंसर और टक्कर चेतावनी प्रणाली जैसे फीचर अनिवार्य करने चाहिए। “भारत वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम” (भारत एनसीएपी) सही दिशा में है, परंतु इसे प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

चौथा कदम, पैदल यात्रियों और गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए सुरक्षित अवसररचना का विकास। हमारे शहरों में फुटपाथ अक्सर गायब हैं या दुकानों और पार्किंग में बदल जाते हैं। सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर पुल और संकेत व्यवस्था से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। कोपेनहेगन और टोक्यो जैसे शहरों की तरह पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए समर्पित मार्ग विकसित करने होंगे।

पाँचवाँ कदम, आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करना। हर पचास किलोमीटर पर ट्रॉमा केंद्र, चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा और हेल्पलाइन के साथ “राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिक्रिया जाल” तैयार किया जा सकता है। उपग्रह आधारित प्रणाली से एम्बुलेंस को शीघ्रतम मार्ग मिल सकता है। निजी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने का दायित्व कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

साथ ही, जनजागरूकता का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा, हेलमेट

और सीट बेल्ट अभियान, तथा मीडिया के माध्यम से निरंतर जनसंवाद से व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जब तक नागरिक स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई भी नीति स्थायी परिणाम नहीं दे पाएगी।

कई देशों में सड़क सुरक्षा को राष्ट्र-निर्माण का अंग माना गया है। स्वीडन की “विजन जीरो” नीति इसका उदाहरण है, जहाँ 1997 से यह लक्ष्य रखा गया कि किसी को भी सड़क पर मरना नहीं चाहिए। इस नीति ने डिजाइन, प्रवर्तन और तकनीक के संयोजन से मृत्यु दर को आधे से अधिक घटा दिया। भारत को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जहाँ मानव जीवन की कीमत सर्वोपरि हो।

अंततः यह स्वीकार करना होगा कि भारत की सड़क सुरक्षा समस्या केवल अवसररचना की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी है। जब तक लोग स्वयं अनुशासन को अपनाने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी कानून कारगर नहीं होगा। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर सामाजिक आंदोलन बनाना होगा।

भारत आज आर्थिक शक्ति बनने को दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर यह विडंबना है कि हर साल लाखों लोग केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमारी सड़कें असुरक्षित हैं। विकास का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति — चाहे वह चालक हो, साइकिल सवार या पैदल यात्री — स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

समय आ गया है कि सड़क सुरक्षा को “परिवहन मुद्दे” नहीं बल्कि “मानव अधिकार मुद्दे” के रूप में देखा जाए। यह केवल गति की नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का सवाल है। हमें तय करना होगा कि भारत की सड़कों पर रफ्तार जीने का प्रतीक क्या मरने का कारण है।

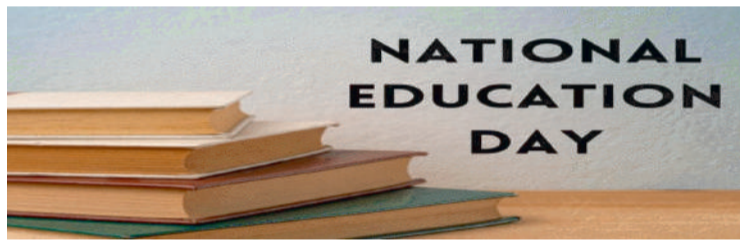
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज

हमारे देश में प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 11 नवंबर 2008 को की गई थी जिसके बाद प्रतिवर्ष यह दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस दिन देशभर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन को स्कूल/ कॉलेज/ शिक्षण संस्थानों में बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है।

किस की स्मृति में शुरू किया गया नेशनल एजुकेशन डे आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। वे 5 अगस्त

1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और साथ ही उनके कार्यकाल में विभिन्न साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का गठन हुआ। इसके साथ ही उनके ही कार्यकाल में सांस्कृतिक संबंध परिषद भी स्थापित हुआ। उनके द्वारा किये गए कार्यों को सारहने के लिए ही इस दिन की शुरुआत की गई।

क्या है महत्व शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। व्यक्ति और समाज दोनों को आकार देने में एजुकेशन की भूमिका मुख्य है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक



किया जा सके और सभी को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए। इसी के चलते भारत सरकार की ओर से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य भारत के सभी स्कूल/ कॉलेज/ संस्थानों को जो मजबूत करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में

मौलाना अबुल कलाम आजाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और बेहतरीन लेखक थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे गांधी जी के समर्थक थे। आजादी से लेकर अगले 10 वर्षों तक वे शिक्षा मंत्री के पद पर कानिज रहे। सन 1952 में वे पहली बार उच्च प्रदेश के रामपुर से सांसद चुने गए थे। इस महान शिक्षाविद का निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ था।

प्रश्न आया है कि पहले हम सांसारिक

संबंधों/कृत्यों में थे अब यदि हम इष्ट के नाम-स्मरण में ही केवल रह जायें तो क्या यह गलत है?

आपका प्रश्न कीमती है। और सामान्यतः यही हम करते हैं। पहले हम एक किनारे से चिपके थे अब दूसरे किनारे से चिपक गये। पहले बाहर/लोगों से/संसार से/संबंधों से/धन-धान्य से चिपके थे, अब पिछले सभी कार्यों/कृत्यों से विमुख होकर, इष्ट-स्मरण के नाम पर रह गये। अभी हम ही असत्य पर हैं तो हमारा इष्ट स्मरण कितना सत्य हो सकता है? तराजु जैसे एक पुलड़े से दूसरे पुलड़े की तरफ झुक जाता है, जैसे घड़ी का पैडलम एक अति से सीधा दूसरी अति पर जाता है, उसी प्रकार एक किनारे से दूसरे किनारे में जाकर चिपक जाना

आसान है। हम मात्र चिपकना ही चाहते हैं, भले एक से या दूसरे से, लेकिन जीवन प्रवाह है, बहने वाला है। वह किसी किनारे से चिपक जाये या उसके विरुद्ध हो जाये तो वह गतिमान नहीं हो सकता। जैसे नदी बीच में बहती है, किनारों को छूती भी है और अछूती भी रहती है, इसी प्रकार जीवन भी प्रवाहित तभी होता है जब वह मार्ग की विभिन्न स्थितियों को छूता भी है और अछूता भी रह जाता है। ध्यान रहे कि जीवन अंतियों/किनारों पर नहीं है, मध्य में बहने में है। किनारों को समतापूर्वक जानने/देखने/समझने/छूकर/तुल्य होकर/ज्ञान लेकर अगली यात्राओं में गतिमान होना ही जीवन है।

जागृत आत्मा का लक्षण सत्यं शिवं सुंदरम

मनुष्य की रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ उसकी अंतः चेतना की साक्षी होती हैं। वे इस बात का पता देती हैं कि उसकी आत्मा प्रसुप्त है या जागरूक। रजागरूक आत्मा का लक्षण है- सत्यं शिवं और सुंदरं की ओर उन्मुखता। प्रसुप्त आत्मा का लक्षण है- इसके विपरीत असत्य, अशिव और असुंदर की ओर गतिमानता। संसार में किसी सुंदर दृश्य, सुंदर स्वरूप और सुंदर गुण को देखकर जिसकी आत्मा प्रसन्न, प्रफुल्ल और उल्लसित हो उठती है उसमें स्वयं भी उस प्रकार का सौंदर्य अपने में पाने की ललक होती है, तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा में जाग्रति का उन्मेष रहा है।

“जागरूक” आत्मा वाला व्यक्ति प्रकृति की गोद में गाते-खेलते पशु-पक्षियों, कल-कल करते झरनों और नदियों, गगनचुम्बी पर्वतमालाओं को देखकर ऐसा आनंद अनुभव करता है मानो सब सुंदर प्रसार उसकी आत्मा से ही प्रभावित होकर फैल गया है। वह उसे उसी प्रकार देखता है, जैसे दर्पण में अपना सुंदर प्रतिबिंब। किसी गायक का सुंदर संगीत, कवि की रचना और चित्रकार कला देखकर आत्मविभोर होकर ऐसा अनुभव करता है मानो गीत, वह काव्य और वह आलेखन उसकी अपनी अनुभूतियाँ और हुईं अपिचिन्तित हों, जिन्हें वह स्वयं प्रकट कर स्वयं ही देख सुन रहा है। जागरूक आत्मा वाले संसार के सारे शिव और तत्त्वों से तादात्म्य का अनुभव करते हैं।

जनेऊ क्या है और इसकी क्या महत्ता है?

*भए कुमार जनेऊ सब आता। दीव जनेऊ गुरु धितु माता ॥

जनेऊ क्या है- आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाँके को से दाँद बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रखते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ तीन धागों वाला एक सूत होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में “यज्ञोपवीत” कहा जाता है।

यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाँके कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात् इसे नले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाँके कंधे के ऊपर रहे।

तीन सूत त्यों- जनेऊ में मुख्यतः से तीन धागे होते हैं। यह तीन सूत देवकण, धितुकरण और केशिकण के प्रतीक होते हैं और यह स्वतः, रज और तम का प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के तीन धराणों का प्रतीक है। यह तीन आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत की त्रार दिया जाता है।

नौ तार- यज्ञोपवीत के एक-एक तार में तीन-तीन तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या नौ होती है। एक मुख्य, दो नासिका, दो आश्र, दो कान, मल और मूत्र के दो द्वारा भित्ताकर कुल नौ होते हैं।

पाँच धागें- यज्ञोपवीत में पाँच गाँठ लगाई जाती है जो ब्रह्म, धर्म, प्रर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह पाँच धागों, पाँच ज्ञानेदियों और पाँच कर्मों का भी प्रतीक भी है।

बैदिक धर्म में प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य को जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे।

जनेऊ की लंबाई- यज्ञोपवीत की लंबाई 9 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 दिशाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए।

चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह इन्द्र, तीन सूत्रग्रंथ, जो अग्रथक भित्ताकर कुल 32 दिशाएँ होती हैं। 64 कलाओं में त्रैसे- वासु निर्माण, व्यंजन

इस तादात्म्य का रहस्य यह है कि मनुष्य की आत्मा सुंदरताओं, कलाओं और श्रेष्ठताओं का भंडार है।

आत्मा में निवास करने वाली विशेषताएँ और गुण किसी माध्यम का आधार पाकर प्रकट होती हैं, किंतु इसका अनुभव होता उसको ही है, जिसकी आत्मा प्रबुद्ध होती है। प्रसुप्त आत्मा वालों को उसका अनुभव उसी प्रकार नहीं होता, जैसे सोये हुए व्यक्ति को उसकी कलाकृति दिखलाने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती।

यह आत्मा की जागरूकता ही है, जो श्रेष्ठता, देवत्व, कला, सौंदर्य और सद्गुणों की अभिरुचि तथा उनके प्रति आनंदमयी अनुभूति को जन्म देती है।

आत्मा में यह विशेषता परमात्मा से अवतरित हुई है। प्रत्येक तत्त्व परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य-विधान में जन्मा है। उसके विचार, उसके गुण और उसकी अनुभूतियाँ परमात्मा-तत्त्व से ओत-प्रोत रहती हैं और यह सारे तत्त्व आत्मा में संकलित रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंश है। उसमें परमात्मा के वे सब गुण होने उसी प्रकार स्वाभाविक हैं, जिस प्रकार बूँद में सागर की विशेषताएँ। मनुष्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त है। यह दूसरी बात है कि उसके अवगुणों और अपकर्मों के कारण उसकी आत्मा जागरण से वंचित हो और वह अपनी नई संपदाओं का अनुभव न कर पाए।

कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, वंश निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आमूयक निर्माण, कृषि ज्ञान आदि। जनेऊ के नियम- 1. यज्ञोपवीत को गल-मूत्र दिसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर घड़ा लेना चाहिए और शयन स्वच्छ करके ही उतरना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कनर से ऊंचा हो जाए और अग्रविष न हो। अग्रने व्राशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार-बार किया जाए।

2. यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 गहरे से अधिक समय हो जाए, तो बदल देना चाहिए। खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर नहीं रखते। धागे केशों और गंदे लेने लगे, तो पहले से बदल देना प्रथित है।

3. यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कच्छ में पकने रखकर ही धुनाकर धो लेते हैं। मूल से उतर जाए, तो प्रायश्चित्त करें।

4. नर्कदा बनाये रखने के लिए उम्रमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधें। इसके लिए निम्न व्यवस्था रखें। बालक जब 3 नव नियमों के पालन करने योग्य हो जाए, तभी त्रिकोण यज्ञोपवीत करना चाहिए।

* धिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाँद कान की बस अंडकोश और मूत्रवेदियों से जुड़ी होती है। नूत्र दिसर्जन के समय दाँद कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है।

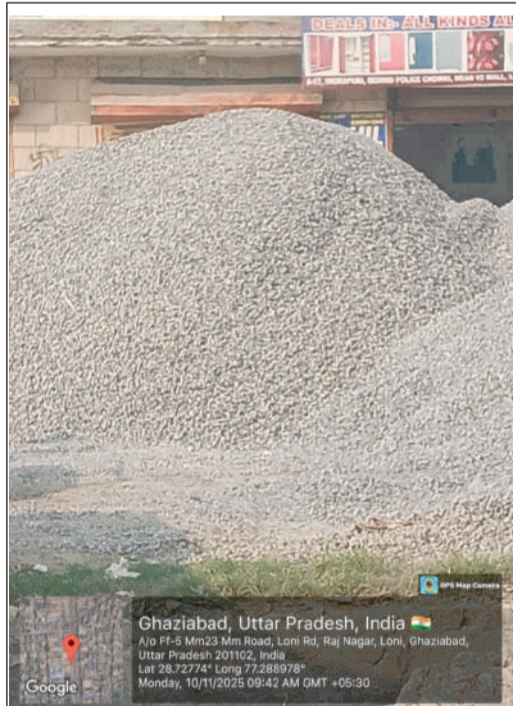
वैदिकों अनुसार बार-बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है।

* कान पर जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूयं नाड़ी का जाग्रण होता है।

* कान पर जनेऊ लपेटने से वेद संबंधी रोम एवं रक्तवाह्य की समस्या से भी बचाव होता है।

* माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत् प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाँद कंधे से लेकर कनर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत् प्रवाह नियंत्रित रहता है जिससे कान-कोष्ठ पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है।

जनेऊ से पवित्रता का अस्सास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है। कंधे पर जनेऊ है, इसका भाव अस्सास लेने से ही मनुष्य अस्वाचार से दूर रहने लगता है।



यह सारा बिलडिंग मेटेरियल दिल्ली सहारनपुर रोड पर रोड की ग्रीन बेल्ट में डालकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। लोनी सबसे प्रदुषित क्षेत्र है यहा.पर ग्रेप सिस्टम लागू होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।

आरडब्ल्यूए हरि कुंज के अनुरोध पर एक सीपीआर सत्र आयोजित किया गया

नवदीप सिंह

रविवार, 9 नवंबर 2025, प्रारंभ समय: 09:00 बजे, समाप्ति समय: 11:00 बजे, स्थान: हरि कुंज अपार्टमेंट, बीएसईएस कार्यालय के सामने, हरि नगर, नई दिल्ली। आरडब्ल्यूए हरि कुंज के अनुरोध पर एक सीपीआर सत्र आयोजित किया गया। यह सोसायटी के सदस्यों के लिए हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में जान बचाने के आपातकालीन विकल्पों के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।

इसलिए, लगभग 20 लोगों को आवश्यकतानुसार सीपीआर चेस्ट कम्प्रेशन देने का ऑन-साइट प्रशिक्षण दिया गया। इस गतिविधि को सभी ने देखा और जीवन जागृति सोसाइटी, एनजीओ ने डीडीएमए (पश्चिम) आपदा मित्र एस. नवदीप सिंह, अध्यक्ष एस. जोगिंदर सिंह, सिविल डिफेंस डी.डब्ल्यू. (राजौरी गार्डन) और चीफ मेट्टर (हरि नगर) और कारी पुरी, पोस्ट वार्डन (पश्चिम विहार) श्री



अशोक ढींगरा जी, डीपीडब्ल्यूएस. दलजीत कलसी, डीपीडब्ल्यू (राजौरी गार्डन) सुखदेव सिंह सैनी जी के साथ जीवन जागृति एनजीओ के सचिव श्री श्रीराम सिंह, श्री फिरोज खान सदस्य और सीडी वालंटियर ने आज के कार्यक्रम में जन जागरूकता के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया।

ये समाज की बेहतरी और सामाजिक उत्थान

के लिए आयोजित किये जाने वाले सत्रों में से एक है। एनजीओ के सभी सदस्यों के साथ-साथ डीडीएमए (पश्चिम), आपदा मित्र, नागरिक सुरक्षा (पश्चिम) और आरडब्ल्यूए ने किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर समाज और राष्ट्र की सेवा करने की मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एनजीओ ने सहयोग से स्कूल, कॉलेज, आरडब्ल्यूए, मॉल, सोसायटियों, औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न सीपीआर सत्र आयोजित किए हैं और हजारों उपस्थित लोगों को मौके पर ही प्रशिक्षण दिया है।

मोटो: “जरूरत के समय की गई मदद अच्छे काम से की गई मदद से कहीं बेहतर है।”

कबीर सेज: “काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब ॥”

के जरिए सूचना: ओंकार पुरी, पुरी कंसल्टिंग एवं एडवाइजरी सर्विसेज और मुख्य सलाहकार

रसिक शिरोमणि हरिराम व्यास महाराज के प्राकट्योत्सव पर किशोर वन में किया गया उनकी समाधि का पूजन



प्रख्यात भजन गायक जे.एस.आर. मधुकर ने किया हरिराम व्यास महाराज द्वारा रचित पदों व भजनों का गायन (डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। बाग बुंदेला क्षेत्र स्थित किशोर वन में चल रहे विशाखा सखी के अवतार हरित्रीयों के आचार्य संत रसिक शेरखर अनन्य शिरोमणि हरिराम व्यास के 515वें चतुर्विंशतीय प्राकट्योत्सव के अंतर्गत पूज्य हरिराम व्यास महाराज की समाधि का देश-विदेश से आए सैकड़ों भक्तों-श्रद्धालुओं के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन-अर्चन किया गया तत्पश्चात संतों व भक्तों के द्वारा समाज-गायन किया गया जिसमें "व्यास वाणी" एवं "ठाकुर युगलकिशोरजी और सखियों के बीच संवाद" के विभिन्न पदों का संगीतमय संस्वर गायन किया रसिक समाज गायन में हरिराम व्यास कृत "रतन जटित पिचकारी भरि-भरि छिरकत चतुर सुजानिह", "मानहुं तरुन तमालहिं लपटो, कनकलता बहुबेलि, गोरोरुन मुख लेप्यो, लिखी छबीली भीहर, "ये ढोटा वृषभानु राय सुवल तुम्हारी सौंहर, "देखति सोभा ब्रजपति रानी, आनन्द मन महं होई, आनु रोहिनी भाग हमारी, ताहिन पूजै कोई" आदि पदों का गायन किया

गया। इससे साथ ही सरस भजन संध्या का आयोजन हुआ जिसमें प्रख्यात भजन गायक जे.एस.आर. मधुकर ने ठाकुरश्री जुगल किशोर महाराज की महिमा से ओत-प्रोत भजनों व हरीराम व्यास महाराज द्वारा रचित पदों का संगीत की मुदुल स्वर लहरियों के मध्य गायन किया। किशोर वन के वरिष्ठ सेवायत आचार्य घनश्याम किशोर गोस्वामी एवं आचार्य जयकिशोर गोस्वामी ने समाज मुखिया, समस्त समाजियों एवं रसप्रियों का अंगवस्त्र, माल्यार्पण, चंदन एवं सुगंधित द्रव्य प्रदान कर सम्मान किया। इस अवसर पर श्रीमहंत बाबा फूल डोल बिहारी दास महाराज, मुखिया प्रेमदास, अलबेली शरण, प्रख्यात साहित्यकार "यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, डॉ. भागवत कृष्ण नांगिया, प्रमुख समाजसेवी गोवर्धन दास अग्रवाल, डॉक्टर ओमजी, समाज मुखिया किशोरी शरण भक्तमाली, पण्डित जगदीश शास्त्री, डॉ. राधाकांत शर्मा, महंत मधुमंगल शरण शुक्ल, संत राधा चरण दास, आचार्य हेमकिशोर गोस्वामी, चंद्र किशोर गोस्वामी, ललित किशोर गोस्वामी, हित किशोर गोस्वामी, उत्कर्ष किशोर गोस्वामी आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

वंदे मातरम् : राष्ट्रभक्ति, एकता और कर्तव्यनिष्ठा का अमर स्वर - वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान

वंदे मातरम् वह अमर मंत्र है जिसने जाति, मत, मजहब और भाषा की सीमाओं से परे जाकर सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान राष्ट्रीय गीत में अपने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है - बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही सिखाया कि अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाना ही सही राष्ट्रसेवा है

आगरा, संजय सागर सिंह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने गीत के रचयिता स्व. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि वंदे मातरम् भारत की भक्ति, शक्ति और एकता की शाश्वत अभिव्यक्ति है। यह गीत न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत रहा, बल्कि आज भी राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रज्वलित करता है। वंदे मातरम् वह अमर मंत्र है जिसने जाति, मत, मजहब और भाषा की सीमाओं से परे जाकर सम्पूर्ण

भारत को एक सूत्र में बांध दिया। राष्ट्रीय गीत हमें अपने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों के प्रति सजग बनाता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही सिखाया कि अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब सन-1905 में ब्रिटिश शासन ने बंग-भंग का निर्णय लिया, तब वंदे मातरम् गीत ने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की नई लहर पैदा की। उस समय यह गीत हर गांव और नगर में प्रभात फेरियों के माध्यम से गुंजाता रहा और क्रांतिकारियों के होंठों पर यह गीत आजादी का मंत्र बन गया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम् गाया यही इस गीत की अमरता का प्रमाण है। श्री खान ने बताया कि यह गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से प्रेरित है, जिसमें अकाल और अभाव से जूझते बंगाल की पीड़ा को सन्यासियों के आंदोलन के माध्यम से स्वर मिला। यही स्वर आगे चलकर भारत की

सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया। 150 वर्षों से वंदे मातरम् भारतीयता और राष्ट्रीयता का प्रतीक बना हुआ है। यह किसी उपानस विधि या व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाता है यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम सब वंदे मातरम् का हिस्सा हैं। यह गीत राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत प्रतीक है, जो हमें अपनी मातृभूमि के प्रति सम्पूर्ण और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। आखिर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी यही संदेश देते हैं कि भारत की प्रगति का आधार केवल अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्यबोध है। इसी कर्तव्य भावना को वंदे मातरम् 150 वर्षों से पुष्ट करता आ रहा है। वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, यह भारत की आत्मा का स्वर है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह इसने सभी देशवासियों में एकता, साहस और बलिदान की भावना जागाई, उसी तरह आज यह हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रप्रेम का शाश्वत प्रतीक बना हुआ है।

पर्यावरण पाठशाला : समाज में बच्चों की भूमिका और जवाबदेही

- डॉ. अंकुर शरण

बच्चे किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव होते हैं। यदि उनमें जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बचपन से विकसित की जाए, तो वही बच्चे आगे चलकर एक जागरूक नागरिक और समाज सुधारक बन सकते हैं। आज का युवा वर्ग और बच्चे एक सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित समाज की कामना तो करते हैं, परंतु उसके निर्माण में उनकी भागीदारी उतनी सक्रिय नहीं दिखती। यह आवश्यक है कि हम बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भी सीख दे ताकि वे अपने कर्मों से बदलाव का हिस्सा बनें।

इसी सोच के साथ 'पर्यावरण पाठशाला' के अंतर्गत समाज में बच्चों की भूमिका और जवाबदेही को केंद्र में रखकर कई विशेष पहलें शुरू की गई हैं। "हर हाथ हरा अभियान" के तहत प्रत्येक बच्चे को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। "मेरा पेड़ - मेरी जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर आधारित यह अभियान बच्चों में प्रकृति के प्रति अपनत्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। वहीं "शांति संदेश दीवार" पहल के माध्यम से बच्चे अपनी रचनात्मकता को चित्रों और संदेशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक विचारधारा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है।

बच्चों की सड़क सुरक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए "रोड सेफ्टी बडी" अभियान चलाया गया है, जिसमें बच्चे अपने स्कूल और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। "मेरा घोंसला - मेरे परिंदे" जैसी पहल पक्षी संरक्षण के प्रति बच्चों में प्रेम जगाने का एक सुंदर उदाहरण है, जिसके अंतर्गत वे अपने घरों और विद्यालयों में घोंसले लगाते हैं तथा गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए जल और दाना उपलब्ध कराते हैं।

इसी तरह "जल साक्षरता अभियान" के माध्यम से बच्चे जल संरक्षण के दूत बन रहे हैं। वे न केवल अपने



घरों में जल बचाने के उपाय अपनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। "अपशिष्ट योद्धा" पहल के अंतर्गत बच्चों को कचरा विभाजन और पुनर्चक्रण (Recycle) के महत्व की शिक्षा दी जा रही है। यह कार्यक्रम उन्हें सिखाता है कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इसके साथ ही "संस्कारशाला" के अंतर्गत बच्चों को मानवीय मूल्यों जैसे - सम्मान, सहानुभूति, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा दी जा रही है। वहीं "प्रकृति दर्शन दिवस" के रूप में हर माह एक दिन बच्चों और अभिभावकों को प्रकृति के साथ समय बिताने और उसकी स्वच्छता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनर्जीओज और पी.एच.ई. एजुकेशन ट्रस्ट के संग "पर्यावरण पाठशाला" का उद्देश्य है - प्रकृति के प्रति जागरूकता को मान-जन तक पहुंचाना। आइए, हम सब मिलकर वह सीख जो हमें पर्यावरण से मिली है, उसी को पर्यावरण को समर्पित करें। क्योंकि प्रकृति से सीखना ही जीवन का सबसे सुंदर पाठ है।

सुंदर समाज की परिकल्पना केवल चाहने से नहीं, बल्कि करने से साकार होती है। जब बच्चे अपने दायित्व को समझे, तभी आने वाला कल हरियाली, स्वच्छता और मानवीयता से भरपूर होगा। इसलिए समय आ गया है कि हम बच्चों को केवल भविष्य का आधार न समझें, बल्कि वर्तमान के सक्रिय साथी के रूप में स्वीकार करें।

कानपुर में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में अक्बल डीपी दीपेंद्र चौधरी की कर्तव्य निष्ठा, कई गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां की कमिश्नर पुलिस योगी सरकार के अनुरूप कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ लगातार सफल मोर्चा खोले हुए हैं, जिसमें दक्षिणी जिले की पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है, जिसका पूर्ण श्रेय पीड़ितों की हर संभव तत्काल सहायता के लिए भी चर्चित अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार यहां के तेज तर्रार और व्यवहार कुशल, कठोर परिश्रम वाले डीसीपी साउथ दीपेन्द्र नाथ चौधरी की नेतृत्व कार्यवाही को ही जाता है, जिसके फल स्वरूप दक्षिण सर्किल में होने वाली हर घटना का न केवल सटीक अनावरण संभव पा रहा है, बल्कि घटनाओं से संबंधित अपराधियों को जेल की हवा खिलाने में भी लगातार सफलता प्राप्त की जा रही है। मतलब ऐसी कोई घटना नहीं है जिसका सटीक खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल ना भेजा गया हो। अगवत करते चले कि अपनी अगुवाई वाली साउथ सर्किल में अब तक लगभग सारी घटनाओं का सटीक खुलासा करवाने के साथ ही अब तक दर्जनों शांतियों को जेल की हवा खिला चुके निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली के जुझारू तेवरों वाले आईपीएस यहां के दक्षिण के पुलिस उपायुक्त दीपेन्द्र नाथ चौधरी पीड़ितों की शिकायतों के निष्पक्ष और पारदर्शी तथा संतोषजनक निस्तारण में भी अक्बल माने जाते हैं। साथ ही बहुत उल्लेखनीय यह भी कि शांति और कानून व्यवस्था के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के मामले में बहुत कठोर परिश्रमी निर्दोष फसे नहीं और अपराधी बचे नहीं जैसे लोकहित की प्रबल विचारधारा वाले सरल, शालीन स्वभाव के जुझारू दीपेन्द्र नाथ चौधरी कानपुर में नियुक्त ऐतिहासिक रूप से पहले ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, जो फील्ड के साथ ही कार्यालय में भी पीड़ितों की समस्याओं के खिलाफ सर्वाधिक समय देते हैं।

और उनके पास जो भी पीड़ित आता है। वह संबंधित समस्या / शिकायत के संतोष जनक त्वरित निस्तारण के फलस्वरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही जाता है। अगर पुलिस द्वारा पीड़ितों की सहायता की बाधा करे तो इस संदर्भ में भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिस आशय की पुष्टि करता है। उसके मुताबिक अगर कोई पीड़ित सहायता के लिए आता है तो इसका मतलब वह कि उससे रूप में ईश्वर, अल्लाह और गॉड ही हमारी, आपकी या किसी की भी अधिकार परीक्षा लेने ही आता है। इस हिसाब से भगवान और भाग्य यानी कर्म बुरोसे रहने वाले आईपीएस दीपेन्द्र नाथ चौधरी अपने कर्तव्य पथ पर हर दृष्टिकोण से सफल नजर आते हैं, जो लोक प्रियता के मामले में भी उन्हें लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनाए हुए है।



एग्री इकाई बना सकती है यूपी को विकसित उत्तर प्रदेश

पंकज जायसवाल

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले कुछ सालों में यूपी की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की शक्ति को अर्थव्यवस्था को लक्षित कर रहे हैं तथा साल 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस अभियान में प्रवासीयों को लक्षित के लिए रिसर्च में भी लगे हैं। ट्रिलियन डॉलर का बजट बजट 90 लाख करोड़ रुपये है जबकि यूपी की वर्तमान जीडीपी लगभग 30.8 लाख करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि यूपी को 1 ट्रिलियन \$ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वर्तमान जीडीपी से 2 गुना अधिक लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्तमान का 30.8 लाख करोड़ भी बड़ी 6 साल में दुगुना हुआ है। यह अर्थव्यवस्था है, यह बिकेन प्रोत्साहन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कर की आसानी के दिग्दर्शन के माध्यम से कर-रिपोर्टिंग सौदों को कटव कर लेने से लगभग दोगुना कर रहे हैं। लॉकडॉउन के दौरान भी, तीन गुना और 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े और को पाठना होगा। यदि सीएम योगी आदित्यनाथ इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें यूपी को दुनिया में छोड़ देंगी और कानून बनाना होगा और प्रदेश को अर्थव्यवस्था राय से निर्वात राय में बदलना होगा।

जलमार्ग, यूपी में प्राचीन नदी परिकल्पना प्रणाली थी और अगर हम इसे पुनर्जीवित करते हैं तो लागत-प्रभावशीलता और परिकल्पना की आवाजाही प्रारंभ शुरू करने में क्रांति ला सकते हैं। अर्थव्यवस्था प्रमुख तरीकों को वैज्ञानिक करने और संरक्षित करने के लिए सरकार को कुछ वृत्तीयों का समायोजन करना होगा। पहली वृत्तीय यह है कि यदि फसल की लागत अधिक होगी तो खाद्य कर्मों पर अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और दूसरी तरह जिससे समाज का मध्य वर्ग प्रभावित होगा और दूसरी तरह अगर फसल की कीमत कम है तो किसान बुरी तरह प्रभावित होगा। दूसरी वृत्तीय यह है कि फसल के नुकसान पर तब तक किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को पाठना चाहिए कि किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है।

व्यक्तिगत फसल सर्वेक्षण आसानी से सके और क्षेत्रवार बीमा सुधारों के बजाय इसे व्यक्तिगत खेती की जमीन के नुकसान के आधार पर दिया जा सके। वृत्तीय जमीनी, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है जमीन के अभाव-ब-दिन छोटा होना। सरकार को जागरूकता शिबिरों का आयोजन करना चाहिए जिसमें उन्हें निम्नलिखित के नुकसान के बारे में बताया जाए। पहली वृत्तीय यह है कि यदि फसल की लागत अधिक होगी तो खाद्य कर्मों पर अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और दूसरी तरह जिससे समाज का मध्य वर्ग प्रभावित होगा और दूसरी तरह अगर फसल की कीमत कम है तो किसान बुरी तरह प्रभावित होगा। दूसरी वृत्तीय यह है कि फसल के नुकसान पर तब तक किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है। किसान को नुकसान नहीं देना चाहिए जो किसान को नुकसान नहीं देता है।

ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित हो -भारत की न्यायिक क्रांति का नया अध्याय

न्यायिक सुधार अब केवल जजों या वकीलों का विषय नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास की रणनीति का केंद्रीय अंग बन चुका है, पीएम के सराहनीय विचार - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी गाँविया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा केवल आर्थिक सूचकांकों या बुनियादी ढाँचों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तथ्य होती है कि वहां कानागरिक कितना सुरक्षित, समान अवसरों से संपन्न और न्याय प्राप्त करने में सक्षम है। भारतीय पीएम ने नई दिल्ली में "कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने में प्रशासनिक सम्मेलन में जो बात कही, ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है, जब ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित हो वह न केवल भारत की न्यायिक नीतियों का नारा है, बल्कि एक लोकोत्प्रेरक दर्शन का सार भी है। (वता में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकको समानअधिकार और कानूनके तहत समान सुरक्षा की गारंटी दे ता है। फिर भी कई लोग अशिक्षा गरीबी प्राकृतिक आपदाओं अपराध या आर्थिक तंगी व अन्य बाधाओं के कारण कानूनीसेवाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। जूजि थॉर्स अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था, इसलिए इसके कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क

कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं को उपलब्धता के क्रम में, इस दिन, देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

साथियों बात अगर हम ईज ऑफ जस्टिस का अर्थ गूढ़ विस्तृत भाषा में समझने की करें तो, यह केवल अदालतों की संख्या बढ़ाने या नए कानून बनाने से नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन से जुड़ा है जो हर नागरिक को यह भरोसा देता है कि न्याय उसके द्वार तक पहुंचेगा, न कि उसे न्याय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह विचार आज के 21वीं सदी के ग्लोबल डेमोक्रेसी प्रभावकों से इसलिए और भी अहम है क्योंकि दुनिया भर में "जस्टिस एक्सेसिबिलिटी" और "लीगल एपावरमेंट" को सतत विकास (एसडीजी-16) के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। भारत की न्याय प्रणाली की यह नई दिशा ईजी ऑफ लिविंग के समानांतर खड़ी है, जहां सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता, पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र में सुधार कर रही है, वहीं न्यायिक सुधार उसकी सबसे संवेदनशील कड़ी है। जैसे आर्थिक उदारिकरण ने उद्योगों को मुक्त किया था, वैसे ही न्यायिक सशक्तिकरण नागरिकों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाता है। (संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय न्याय आयोग की रिपोर्टें लगातार यह दर्शाती रही हैं कि किसी भी देश का 'ईजी ऑफ जस्टिस' इंडेक्स संकेतक लोकतंत्र की गुणवत्ता का सबसे प्राणमणिक संकेतक होता है। भारत इस दिशा में "डिजिटल जस्टिस", "लीगल एड डिजिटली वरी मैकेनिज्म" और "जस्टिस एट डोरस्टेप" जैसे अभियानों के माध्यम से एक ऐसे

मॉडल का निर्माण कर रहा है जो न केवल विकासशील राष्ट्रों बल्कि विकसित देशों के लिए भी प्रेरक बन रहा है।

साथियों बात अगर हम जब भारत स्वयं को एक विकसित देश के रूप में देखेगा, तब हमारी न्याय व्यवस्थाकैसी होनी चाहिए इसको समझने की करें तो, "जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे, तो हमारा जस्टिस डिजिटल सिस्टम कैसा होगा?" वास्तव में भारत की विजय 2047 को दृष्टि का सबसे मूल प्रश्न है। विकसित राष्ट्र केवल जीडीपी, तकनीकी प्रगति या वैश्विक प्रभाव से नहीं बनता; बल्कि वह तब विकसित कहलाता है जब उसका नागरिक भरोसे से कह सके कि उसे समय पर, निष्पक्ष और सुलभ न्याय मिलेगा। भारत के न्यायिक तंत्र की आज जो चुनौतियाँ हैं, लंबित मामलों का बोझ, जटिल प्रक्रिया, कमजोर कानूनी सहायता तंत्र, और डिजिटल असमानता उन्हें दूर किए बिना "डेवलपड इंडिया" की परिकल्पना अधूरी है। इसी पृष्ठभूमि में "ईज ऑफ जस्टिस" का नारा एक नीतिगत क्रांति का संकेत देता है। पहला स्तंभ, न्याय का डिजिटलीकरण-सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक "ई-कोर्ट परियोजना" ने भारत की न्याय प्रणाली को तकनीकी रूप से नया स्वरूप दिया है। आज 18 करोड़ से अधिक केस रिपोर्ट डिजिटलाइज हो चुके हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा ने दूरस्थ इलाकों के नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ा है। "नेशनल जूडिशियल डेटा ग्रिड" विषय का सबसे बड़ा कंस- डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्याय सुधार रिपोर्टों में मॉडल के रूप में उद्धृत किया जा चुका है। दूसरा स्तंभ-कानूनी सहायता का सार्वभौमिकरण-भारत का नेशनल लीगल

सर्विसेज अथॉरिटी अब केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों महिलाओं, श्रमिकों, दिव्यांगों, आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों, तक कानूनी सहायता पहुंचाने का मिशन लेकर चल रहा है। भारतीय पीएम द्वारा इस तंत्र को "लीगल एड डिजिटली वरी मैकेनिज्म" के रूप में सुदृढ़ करने का आह्वान यह संकेत है कि न्याय अब एक सेवा है, विशेषाधिकार नहीं। तीसरा स्तंभ-पारदर्शी व जवाबदेह न्यायिक ढांचा-विकसित भारत में न्याय केवल "कानूनी व्याख्या" का विषय नहीं रहेगा, बल्कि यह "नागरिक अनुभव" का हिस्सा बनेगा। जैसे 'इज इंग्लिज बिजनेस' ने व्यापारिक नीतियों को सरल बनाया, वैसे ही 'ईज ऑफ जस्टिस' न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और नागरिक संवाद को प्राथमिकता देगा। जस्टिस भविष्य का डेवलपड इंडिया। हिस्टोरिक मॉडल ऐसा होगा जहाँ—एफआईआर से लेकर फैसले तक की प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक की जा सके, वकील, जज और पीड़ित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवाद कर सकें, और न्यायालयों में "मानवीय संवेदना" को कानूनी प्रक्रिया से ऊपर स्थान दिया जाए। यह वही परिवर्तन है जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ "ह्यूमन सेंटरड जस्टिस" कहती हैं, जहाँ कानून केवल नियंत्रण का नहीं, बल्कि संरक्षण का माध्यम होता है।

साथियों बात अगर हम कानूनी सहायता वितरण तंत्र की मजबूती, लीगल सर्विसेज डे और न्यायिक व्यवस्था का नया सामाजिक मिशन को समझने की करें तो, भारत में हर वर्ष 9 नवंबर को "लीगल सर्विसेज डे" मनाया जाता है, जो 1987 के "लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट" की वंशपति है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि न्याय

तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को हर व्यक्ति तक पहुंचाए। भारतीय पीएम का यह कथन लीगल एड डिजिटली वरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा कार्यक्रम, हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। वास्तव में भारत की सामाजिक न्याय यात्रा का घोषणापत्र है। भारत का लीगल एड मिशन- भारत में 15 लाख से अधिक लोगों को हर वर्ष मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। "टेली-लॉ" जैसी डिजिटल योजनाओं ने 15 हज़ार से अधिक पंचायतों तक कानूनी सहायता की पहुंच बनाई है। इन प्रयासों से भारत एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा है जिसे "जस्टिस डिजिटली एट लास्ट माइल" कहा जा सकता है। ग्रामीण भारत में न्यायिक जागरूकता का विस्तार- पीएम के विजन के अनुरूप अब न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर "लीगल एड क्लीनिक" और "न्याय सखी" जैसी पहलें ग्रामीण स्तर पर न्यायिक साक्षरता का विस्तार कर रही हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की "एक्सेस टू जस्टिस फॉर आल" नीति के अनुरूप है, जो कहती है कि न्याय सभी प्रभावी है जब वह स्थानिय स्तर पर सुलभ हो। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत की पहल को समझने की करें तो विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लीगल एपावरमेंट फ्रेमवर्क दक्षिण एशिया में सबसे उन्नत है। "टेली-लॉ", "ई-कोर्ट्स", "ई-परिसंस" और "लीगल एड चाटबोट्स" जैसी योजनाएँ वैश्विक न्यायिक सुधार एजेंडा में उदाहरण के रूप में शामिल की



राजनैतिक व्यंग्य-समागम : 1. हम हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी! : राजेंद्र शर्मा

यारों, न विरोधी समझे हैं न समझेंगे मोदी जी की बात! बताइए, मोदी जी के विरोधी ब्राजील की मॉडल की हरियाणा की मतदाता सूची में एंटी तक का स्वागत करने को तैयार नहीं हैं। उल्टे इसके वोट चोरी का सबूत होने का शोर मचा रहे हैं। मोदी जी की इच्छा से ज्ञानेश बाबू अगर मतदाता सूची को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ एक प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के और सिर्फ अपने देश के ही नहीं, परदेश के भी लोगों के भी चेहरे लाने में लगे हुए हैं, तो किसलिए? जाहिर है कि भारत की डेमोक्रेसी को इंटरनेशनल बनाने के लिए। आखिर, हमारी डेमोक्रेसी, मदर आफ डेमोक्रेसी है या नहीं?

पर सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने से ही क्या होगा? दुनिया से मनवाना भी तो पड़ेगा कि डेमोक्रेसी की मम्मी हमारे पास है। वना जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? और दुनिया हमारे कहने से ही थोड़े ही मान लगेगी हमारा पास डेमोक्रेसी की मम्मी है। दुनिया सबूत मांगेगी। और अब हम भी उसके मुंह पर सबूत दे मारने की स्थिति में होंगे। हमारी मतदाता सूची में ब्राजीलियाई मॉडल का नाम है और वह भी एक बार नहीं, बार-बार, पूरे बाईस बार! और किसी देश में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मतदाता सूची होगी क्या? और सुनते हैं कि ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर के साथ, दर्जनों वोट पड़े भी थे। यानी हरियाणा में डेमोक्रेसी को ब्राजीलियाई मॉडल ने जमकर सहारा दिया है।

होने को तो दुनिया में डेमोक्रेसी में और बहुत कुछ भी है, बहुत सी वराइटी हैं। अमरीका के ट्रंप और तुर्किए के एर्दोआ जैसे कहने को चुनाव से बने राष्ट्रपति हैं, जो खुद को पुराने जमाने के बादशाहों से कम नहीं समझते हैं। पंडास में पाकिस्तान जैसे और आगे बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव हैं, जिनमें चुनाव तो होता है, लेकिन विपक्ष नहीं होता है। और तो और नेतन्याहू जैसे नेता भी हैं, जो नेता तो चुनाव से बने हैं, पर ऐसे चुनाव में जिसमें जिस आबादी पर राज कर रहे हैं, उसके बड़े हिस्से को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी-ऐसी ढीली डेमोक्रेसी भी हैं, जहां नागरिक को वोट देने का मौका मिलता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। और भी बहुत कुछ। पर मतदाता सूची के ऐसे अंतर्राष्ट्रीयकरण को हमारे जैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेंगे।

दुनिया झूठ मारकर मानेगी -- यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी!

फिर ही हमारी मतदाता सूचियों में ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लक्षण और भी बढ़ते हैं। सुना है कि हरियाणा में ही मतदाता सूची में एक माताजी के फोटो के साथ पूरे 222 वोट पाए गए हैं। लाखों वोट हैं, जिनका पता संख्या वाला सूची है या अक्षरों में शून्य है यानी अ, ब, ख, द शून्य। हजारों वोट, छोटे-छोटे घरों में सैकड़ों की तादाद में, मुर्गियों की तरह भी नहीं, शायद कबूतरों की तरह रहते हैं। हजारों वोट हैं, जिन्हें एक व्यक्ति एक वोट की कैद

मंजूर नहीं है और एक व्यक्ति, अनेक वोट बनकर रहने की आजादी पसंद करते हैं, आदि, आदि। बेशक, ये सब भी हैं तो डेमोक्रेसी की मम्मी वाले लक्षण ही। फिर भी जो वजन ब्राजीलियाई मॉडल को भारतीय जनतंत्र का महत्वपूर्ण सहारा बनाने में है, वह दूसरे छोटे-मोटे लक्षणों में कहा है!

लेकिन, कोई इससे यह नहीं समझे कि हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दावा सिर्फ अनाड़ी मतदाता सूचियों पर ही टिका हुआ है। हरिजन नहीं। वैसे हमारी मतदाता सूचियों का अनोखापन भी सिर्फ किसी ब्राजीलियाई मॉडल का मोहताज नहीं है। बेशक, मोदी जी की ही इच्छा से, ज्ञानेश गुप्ता जी के विशेष शुद्धिकरण की गंगा में नहाकर निकली मतदाता सूचियों तो अपने आप में एक अजूबा है। देखा नहीं कैसे बिहार में एक-दो नहीं, दस-बीस नहीं, सैकड़ों नहीं, दसियों हजार लोग जब पहले चरण में गांव-गोहल्ले के नजदीक के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि मतदाता सूचियों को तो उनके नाम से ही शुद्ध कर दिया गया है। जाहिर है कि गरीब-गुरबा की गंदगी जितनी कम होगी, सूची उतनी ही ज्यादा स्वच्छ होगी। मतदाता सूचियों को जो सफाई कराने की बीस साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, वह सफाई मोदी-ज्ञानेश की जोड़ी करा रही है और ऐरों-गैरों से मतदाता सूची को स्वच्छ करा रही है।

लेकिन, स्वच्छता लाने का मतलब सिर्फ कूड़ा-कंकट हटाना ही थोड़े ही है। स्वच्छता का मतलब मतदाता सूचियों में सलमा-सितारे टांकना भी है। जुगल जोड़ी ने सूचियों में सितारे भी खूब ही टांके हैं। तभी तो मोदी जी की पार्टी के पूर्व सांसद, पहले सांसद के चुनाव में और फिर इसी साल के शुरू में विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में वोट डालने के बाद, साल खत्म होने से पहले ही बिहार में वोट डाल आए। और सिर्फ पूर्व सांसद जी ही थोड़े ही, मोदी जी की पार्टी के दूसरे कई नेता, दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाल आए। और उत्तराखंड समेत दूसरे कई राज्यों के नेता भी। और ये तो वो नेता हैं, जो डोल पीटकर, राज्य बदल-बदलकर वोट डालते देखे गए। जो सैकड़ों किसी ब्राजीलियाई मॉडल या किसी बुजुर्ग दादी की फोटो के पीछे छुपकर वोट डाल आए होंगे, उनका क्या? ऐसे टूरिस्ट वोट भी दुनिया में और कहाँ मिलेंगे? दुनिया क्या अब भी हमें डेमोक्रेसी की मदर नहीं मानेगी!

वैसे डेमोक्रेसी की मदर होने के साक्ष्य और भी बहुत हैं। हमारे जैसा तटस्थता-मुक्त चुनाव आयोग दुनिया में कहीं और होगा, क्या? विशेष ट्रेनों में भर-भरकर, दूसरे राज्यों से मतदाताओं को जैसे मोदी-शाह पार्टी बिहार के चुनाव के लिए लायी है, वैसे दुनिया में और कहीं लाने दिया जाता होगा क्या? सरायरंजन में वीवीपैट की हजारों पंथियों जैसे खेतों में पड़ी मिली हैं, वैसे वीवीपैट वाली मशीन से कहीं और चुनाव कराया जाता होगा क्या? जैसे यहाँ-वहाँ ईवीएम के स्ट्रॉग रूमों में बिजली जाने और



कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के X हैंडल से साभार

सीसीटीवी बंद होने और संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें आयी हैं, उस सब के बाद भी चुनाव आयोग कान में तेल डालकर कहीं और सोया रहता होगा क्या?

दुनियावालों, मोदी जी-ज्ञानेश जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलवाने के लिए, अब और क्या करना होगा?

(*व्यंग्यकार वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक हैं।*)

2. हम सच नहीं बोलेंगे: विष्णु नागर

चाहे जो कर लो, चाहे जितना एक्सपोज कर दो, झूठ तो हम बोलेंगे ही, फ्राड तो हम करेंगे ही। रुकेंगे नहीं। आप ही बताइए, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, बालसाजी नहीं करेंगे तो, फिर यह काम हमसे बेहतर कौन करेगा? जितना फर्स्ट क्लास झूठ बोलना हमें आता है, किसी और को आता है? अब चुनाव आयोग को नहीं मिले बिहार में घुसपैठिए तो वह जाने, यह उसकी नालायकी है! अभी आधे बिहार में वोट पड़ने वाले हैं जनाब, घुसपैठियों वाला झूठ तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। हमने हर जगह यह झूठ बोला है, तो बिहार को क्यों छोड़ देंगे? आखिर बिहार भी तो अपना है!

हम 'असत्य वीर' जब झूठ के मैदान में उतरते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटते। इस देश और इसके बचे-खुचे लोकतंत्र की ऐसी-तैसी करके ही हम दम लेंगे। अभी तो ट्रेलर ही देखा है तुमने। फिल्म तो अभी हमने रिलीज ही नहीं की है। जब रिलीज करेंगे, तो अच्छे-

अच्छों के होश उड़ जाएंगे!

हमारे प्रधानमंत्री जी तो आदतन झूठ बोलते ही हैं। हमारे गृहमंत्री जी उनके सच्चे अनुयायी हैं। हमारे रक्षामंत्री कुर्सी-रक्षा यज्ञ में आहुति देते हुए दो कदम आगे बढ़कर झूठ बोलते हैं। बुलडोजरनाथ जी का तो धर्म ही है झूठ बोलना। वह पीठाधीश्वर हैं, तो झूठ उनके मुंह से बहुत सुहाना भी है। हिमंत बिस्वा सरमा जी संघ की शरण में आए, नये-नये मुल्ला हैं, ज्यादा प्याज नहीं खाएंगे, तो पद पर कैसे रहेंगे? झूठ हमारी अमूल्य संपदा है। और झूठ बोलने में हमें आम जितनी सुविधा है, सुरक्षा है, चर्चा है, वह कल हो, न हो। आज सीबीआई, ईडी, अदालत सब हमारी है। कल अगर किसी और की हो गई तो!

मान लिया कि हम भाजपाई भी पूरे बिहार में केवल 16 घुसपैठिये ढूंढ पाए। उसमें से भी जांच के बाद चुनाव आयोग ने केवल तीन को संदिग्ध माना, मगर इस कारण हम अपना गुण-धर्म छोड़ नहीं सकते! झूठ ही संघ-भाजपा के प्रान हैं, उसकी सत्कार और संस्कृति है, आचरण की उसकी शुद्धता है। झूठ से हमारी सौ साल पुरानी रिश्तेदारी है। झूठ तो हम बोलेंगे ही। एक बार नहीं, हजार बार बोलेंगे। हजार बार से भी काम नहीं चला तो, लाख बार बोलेंगे, मगर जब भी, जहाँ भी, जिस युग में भी बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे!

जब तक देश में एक भी मुसलमान है, हम झूठ बोलेंगे। जब तक इस देश में एक भी सच जिंदा है, हम झूठ बोलेंगे। जब तक महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष बोस का नाम है, झूठ बोलेंगे। संविधान की शपथ लेकर भी हम झूठ ही बोलेंगे। भारत माता की जयकार करते हुए भी हम झूठ ही बोलेंगे। तिरंगा



हाथ में लेकर भी हम झूठ ही बोलेंगे। राम का नाम लेकर झूठ पहले भी खूब बोला है, आगे भी बोलेंगे। फ्राड बिहार में किआ है और फ्राड आगे भी करते रहेंगे! हम 1947 के बाद के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसलिए झूठ बोलेंगे। झूठ हम हजारों और लाखों मुंह से बोलेंगे। सैकड़ों टीवी चैनलों से बोलेंगे। सोशल मीडिया-आईटी सेल के माध्यम से झूठ के परनाले बहाएंगे। झूठ असंसदीय शब्द है, इसलिए संसद में हम झूठ नहीं, असत्य बोलेंगे। राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को हम 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बताएंगे। झूठ का डंका पूरे विश्व में बजाएंगे। हिटलर और गोकुलसिंह की आत्मा को जगाएंगे।

घुसपैठियों के नाम पर हम चार साल पहले भी असम में झूठ बोल चुके हैं। वहाँ हमारा झूठ जीता। अब भी वहाँ हम झूठ को विजय दिलाएंगे। सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय झूठ है - 'विकास'। बिहार में 'विकास' जारी रहेगा, फिर हम वहाँ से उसे उठाकर असम ले जाएंगे। बिहार को नंबर वन बनाया है, फिर असम को नंबर वन बनाएंगे। इस तरह हर राज्य को नंबर बनाते हुए खुद को नंबर वन बनाते जाएंगे। नंबर टू, थ्री, फोर के लिए हमारे एजेंडा में जगह नहीं है।

हमने पश्चिम बंगाल को भी झूठ बोला था, मगर वहाँ पिट गया था। फिर अगले साल मौका आ रहा है, फिर झूठ बोलेंगे। इस बार झिंजुर की तरह डट कर बोलेंगे। हमने झारखंड में भी यही झूठ बोला था, मगर वहाँ नहीं चला तो क्या हुआ, दिल्ली में तो चल गया, वहाँ तो हमने सरकार बना ली। सच भी हर बार काम जीत पाता है, तो झूठ हार गया, तो क्या गम हो गया! इसलिए 'झूठ के प्रयोग' हम जारी रखेंगे। हम झूठ का साथ मरने तक निभाएंगे। काली टोपी की कसम, हम झूठ बोलेंगे। खाकी की निक्कर की सौगंध, हम झूठ बोलेंगे। डंडे की शपथ, हम झूठ ही झूठ बोलेंगे। नागपुर में हमारे मुख्यालय की सौगंध, हम झूठ बोलेंगे।

ऐसा-वैसा नहीं, हर बार पहले से बड़ा और नया झूठ बोलेंगे। झूठ ने हमें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया

है। हम न यह शीर्ष छोड़ेंगे, न झूठ छोड़ेंगे। हमने झूठ के साथ सात फेरे लगाए हैं, हम इसके साथ जिंदगी भर के 'पवित्र बंधन' में बंधे हुए हैं, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मरने पर 'झूठ की समृद्ध विरासत' देश के लिए छोड़ जाएंगे। हमारे बाल-बच्चे इसके दम पर मौज करेंगे!

हम आजादी की लड़ाई के बारे में झूठ बोलेंगे।

हम मुगलों के बारे में झूठ बोलेंगे। हम छुकार गांधी जी के बारे में भी झूठ बोलेंगे। हम नेहरू के बारे में सीना फुलाकर झूठ बोलेंगे। हम अंबेडकर के बारे में भी झूठ बोलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी दिशाओं में झूठ बोलेंगे। सुबह, दोपहर, शाम झूठ बोलेंगे। हम 'मन की बात' में झूठ बोलेंगे और फिर समूह में रामकथा की तरह उसका श्रवण कर उसका विडियो वायरल करेंगे। हम राष्ट्र के नाम संदेश में झूठ बोलेंगे। हमने लाल किले से हमेशा संसद झूठ बोला है और आगे भी बोलेंगे। लाल पर सफेद खूब फबता है न!

झूठ से सारे देश के वातावरण को प्रदूषित कर देंगे। हम झूठ को सच के साथे से दूर रखेंगे। झूठ का पीछा हम सच के जिंदा रहने तक नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान-विज्ञान की किताबों में हम झूठ हगेंगे, झूठ मूर्तेंगे। झूठ का ही कुल्ला करेंगे। हम स्कूलों-कालेजों को दुर्गंध से भर देंगे और दुर्गंध का नाम सुगंध कर देंगे। हम किसी के धड़ को किसी और के सिर से जोड़ेंगे और उसका रिश्ता धर्म से जोड़ देंगे। हम झूठ को सनतनी आदत बना देंगे। हम झूठ की कार्बन-डाई-ऑक्साइड से गरीबों को मार देंगे। मुसलमानों को फना कर देंगे। दलितों को उनकी 'असली जगह' फिर से बताने देंगे। झूठ की अनश्वरता में हमारा विश्वास अटल है। हम सत्य की ऐसी-तैसी न कर दें, तो फिर कहना कि हम झूठ की असली औलाद नहीं! हम झूठ बोलेंगे, केसरिया को तिरंगे के ऊपर बुलंद रखेंगे।

(*कई पुरस्कारों से सम्मानित विष्णु नागर साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार हैं। जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।*)

सूडान में मानवता रो रही, दुनिया चुपचाप देख रही

राजेश कुमार पारसी

इस समय दुनिया दो युद्धों में ही रही तबाही से चिंतित है। एक युद्ध इजराइल और हमसास के बीच चल रहा है तो दूसरा युद्ध यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है। इन दोनों युद्धों को रूकवाने की कोशिश दुनिया की कई शक्तियां कर रही हैं। दूसरा सच यह है कि ये युद्ध भी इन्हीं में से कुछ शक्तियों की देन है। दुनिया का ध्यान धीरे-धीरे उस युद्ध की तरफ जा रहा है जो कि सूडान में चल रहा है। अजीब बात यह है कि गाजा से कहीं ज्यादा तबाही, उससे कुछ ही दूरी पर सूडान में चल रही है। दूसरी बात यह है कि दोनों जगहों पर नरसंहार लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ था लेकिन दुनिया सूडान की तरफ देखने को तैयार नहीं है। सूडान में मानवता रो रही है, धीरे-धीरे सिपाक रह गई है, लेकिन शांति के मसौदा उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं हैं। वहाँ महिलाओं का बलात्कार करने के लिए उनको ट्रकों में भर-भर कर अपने ठिकानों में ले जाया जा रहा है। कई दिनों तक उनको नौचने के बाद कहाँ फेंका जा रहा है, कोई नहीं जानता।

जिंदा लोगों को जबर्दस्ती ताबूत में बंद करके दुनिया जा रहा है। कई जगहों पर लोगों को समूह बनाकर खाइयों में धकेलकर गड्डों में डाला जा रहा है। इसके बाद उनको गोलीयों से भूनकर, दफन किया जा रहा है। जगह-जगह कल्लेआम हो रहा है, जैसे जानवरों को एक-एक करके काटा जाता है, कुछ ऐसा ही मंजर सूडान की जनता देख रही है। लोगों को पेड़ा पर लटकवा फांसी दी जा रही है। बच्चों को दौड़ा-दौड़ा कर शिकार किया जा रहा है। गाड़ियों से जिंदा कुचलकर मारा जा रहा है। दुनिया के इतिहास में पहली बार नरसंहार के सबूत फोटोलाइव से देखे गए हैं, इसलिए इस पर चर्चा शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर रूंद हो पा जाती है। लगभग सारे अस्पताल बंद हो गए हैं, जिसके कारण लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में लोग चले गए हैं, जहाँ इतनी भीड़ है कि खाने-पीने तक का सामान नहीं बचा है। एक कराइ से ज्यूना लोगों को अस्पताल पड़ोसी देशों में शरण ले ली है जहाँ पहले ही गरीबी है। दो सैन्य गुटों की लड़ाई में आम जनता मारी जा रही है। नरसंहार इतना बड़ा है कि लाशों को छुपाने के लिए उन्हें गड्डों में दबाया जा रहा है। इसके बावजूद जगह-जगह लाशों के ढेर लगे हुए हैं।

पिछले दो साल से इजराइल और हमसास के युद्ध में लगभग 60000 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इससे कम नहीं आंवां, जिसके कारण लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में लोग चले गए हैं, जहाँ इतनी भीड़ है कि खाने-पीने तक का सामान नहीं बचा है। एक कराइ से ज्यूना लोगों को अस्पताल पड़ोसी देशों में शरण ले ली है जहाँ पहले ही गरीबी है। दो सैन्य गुटों की लड़ाई में आम जनता मारी जा रही है। नरसंहार इतना बड़ा है कि लाशों को छुपाने के लिए उन्हें गड्डों में दबाया जा रहा है। इसके बावजूद जगह-जगह लाशों के ढेर लगे हुए हैं।



मुश्किल है। जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को पटक-पटक कर मारा जा रहा हो, वहाँ के हालातों के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। सवाल है कि पूरी दुनिया गाजा के लिए परेशान है जबकि उससे कहीं ज्यादा बर्बरता सूडान में की जा रही है। फिर पूरी दुनिया दो साल से चुप क्यों है।

मानवधिकारों के सबसे बड़े योद्धा अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देश सूडान की तरफ देखने को तैयार नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र को सूडान की चिंता क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात, गाजा के मुस्लिमों की लाशों पर पूरी दुनिया के मुस्लिम देश आंसू बहा रहे हैं। मुस्लिम जगत में बार-बार मांग उठती है कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा क्यों नहीं कर देते। ईरान के साथ इजराइल की झड़प भी हो चुकी है। इसके अलावा यमन के विद्रोहियों ने भी इजराइल पर कई मिसाइल हमले किये हैं। दुनिया भर के वामपंथी और सेव्युलर संगठन भी गाजा की हिंसा के कारण इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। फिलिस्तीनियों से कई गुना ज्यादा सूडानी मुस्लिम मारे जा चुके हैं लेकिन मुस्लिम देश बिल्कुल चुप हैं। भारत में एक मुस्लिम की हत्या हो जाये तो भारत को मुस्लिमों के लिये खतरनाक देश करार दिया जाता है। कश्मीर में आतंकवादियों के मारे जाने पर भी भारत पर सवाल खड़ा किया जाता है। सूडान में लाखों लोगों की हत्या की जा चुकी है और निरंतर जारी है, लेकिन मुस्लिम जगत की चुपि नहीं टूट रही है। आतंकवादियों के मारे जाने से परेशानी है लेकिन मासूम बच्चों की हत्याओं पर चुपची है।

सवाल यह है कि सूडान में इतनी हिंसा क्यों हो रही है और इसमें कौन-कौन से देश जुड़े हुए हैं। वास्तव में सूडान में एक ऐसा गृहयुद्ध चल रहा है जिसमें एक तरफ वहाँ की सेना एसएफएफ है तो दूसरी तरफ वहाँ का अर्ध-सैनिक बंग आरएफएफ है। दोनों सूडान पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं और आपसी लड़ाई में एक दूसरे के समर्थकों को मार रहे हैं। सूडान की हिंसा में बड़ा योगदान आरएफएफ का है जो सेना के खिलाफ

लड़ रहा है और कब्जे वाले क्षेत्रों में आम जनता को निशाना बना रहा है। आरएफएफ का नेतृत्व दोगोलो कर रहा है जबकि सेना का नेतृत्व बुरहान के हाथ में है। सूडान की 97% जनसंख्या सुन्नी मुसलमान है, इसलिए इस धर्म की जंग भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ये पूरी तरह से सत्ता की लड़ाई है। फिर सवाल उठता है कि अगर सत्ता की लड़ाई में आम मुस्लिम मारे जा रहे हैं तो मुस्लिम देश चुप क्यों हैं। सच्चाई यह है कि ये मुस्लिम देश इसलिए चुप हैं क्योंकि यही देश इस लड़ाई को चला रहे हैं। विडम्बना यह है कि ये देश गुप्त रूप से सूडान के दोनों गुटों की मदद कर रहे हैं।

सवाल यह है कि ये मुस्लिम देश सूडान को मदद क्यों कर रहे हैं। वास्तव में सूडान में सोना और कूड ऑयल के अलावा कई कीमती धातुओं के भंडार हैं लेकिन असली लड़ाई सोने को लेकर ही है। इसके अलावा ये देश सूडान के जरिये लाल सागर के इलाके में अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। ये देश इन गुटों को सीधे मदद करने की जगह तस्करी के माध्यम से हथियार और जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे हैं। सूडान की सेना एसएफएफ को इजिप्ट, तुर्की और ईरान मदद दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आरएफएफ को लीबिया और यूएई समर्थन दे रहे हैं। इस समय आरएफएफ ही नरसंहार कर रहा है, इसलिए उसको समर्थन देने के कारण मुस्लिम समाज यूएई को कोस रहा है। उसको सोशल मीडिया पर मुस्लिम लानत भेज रहे हैं। ईरान सेना का समर्थन इसलिए भी करता है क्योंकि उसके कब्जे में सूडान के पीट है। ईरान इस पीटर्स का इस्तेमाल यमन के हथियार सप्लाई करने के लिए करता है। वास्तव में सूडान में मुस्लिम देश अपने निजी स्वार्थों के लिए दोनों गुटों के साथ खड़े हैं। सूडान का सोना ही सूडान की जनता की मुसीबतों की जड़ है। इस सोने को पाने के लिए ही मुस्लिम देश बेशर्मी के साथ सूडानी जनता का खून बहा रहे हैं। मुस्लिम देश इन दोनों गुटों की मदद बंद कर दें तो इनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। विडम्बना यह है कि ये देश सूडान के दोनों गुटों से सोना खरीदकर उन्हें हथियार दे रहे हैं। जिस

सोने का इस्तेमाल सूडान की जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल उसका ही खून बहाने के लिए किया जा रहा है।

सवाल यह है कि जो मुस्लिम जगत किसी भी देश में मुस्लिमों की हत्या होने पर हंगामा करता है, वो सूडानी मुसलमानों के नरसंहार पर चुप क्यों है। संकल्प और वामपंथियों की जुगत पर ताला क्यों लगा हुआ है। वास्तव में सूडान की हिंसा में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, इसलिए इसकी अनदेखी की जा रही है। गाजा में मुस्लिम बनाम यहूदी चल रहा है इसलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं। कई मुस्लिम देश मुस्लिम मुस्लिम देशों का उन्पीड़न कर रहे हैं और उन्हें उनके मानवीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है लेकिन कभी किसी मुस्लिम देश ने इस पर चिंता व्यक्त नहीं की और न ही कभी कुर्दों के लिए आवाज उठाई। इसी तरह पाकिस्तान बलोचों पर जमकर अत्याचार कर रहा है। उनकी नस्ल ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मुस्लिम जगत इस पर बोलने को तैयार नहीं है। चीन अपने देश में रहने वाले उइगर मुस्लिमों का उन्पीड़न कर रहा है लेकिन चीन से जुड़े निजी हितों के कारण सारे देश चुप हैं।

समस्या यही है कि मुस्लिम उन्पीड़न के नाम पर अमेरिका, यूरोप और मुस्लिम देश अपना एजेंडा चलाते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने से लगता है कि मुस्लिमों की बहुत चिंता है लेकिन इस चिंता के पीछे सबके अपने-अपने स्वार्थ हैं। मुस्लिमों से हमदर्दी जताने के लिए कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मुस्लिम समाज ही सोचें कि उससे सबसे ज्यादा नुकसान कौन हो रहा है। भारत में मुस्लिम, मुस्लिम देशों से भी ज्यादा सुरक्षित और आजाद हैं लेकिन यह विमर्श लगातार चलाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिम खतरों में हैं। सूडान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुस्लिम हितों को नमान पर जो देश शरण मचाते हैं और मुस्लिम जगत के रहनुमा बनना चाहते हैं, असंभवतः वो अपने निजी स्वार्थों के लिए खुद भी मुस्लिमों का खून बहा सकते हैं।

उत्तराखंड नरेंद्र मोदी के हृदय में बसता है

तरुण किजय

वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठित यह राज्य पहाड़ी महिलाओं के अभूतपूर्व आंदोलन से गुजरा था। अटल जी ने ठीक ही कहा था कि इस राज्य का जन्म मां की शक्ति से हुआ है। मातृ-शक्ति ने नया राज्य बनाया, जिसमें बड़ी आकांक्षाएं और उम्मीदें थीं। हिमालयी राज्य की महिलाओं के सपनों को साकार करना बाकी है।

हिमालय में संन्यासी बनते-बनते से लेकर उत्तराखंड निर्माण की रजत जयंती समारोह के उद्घाटन तक, नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में एक पूरा किताब लिखी है। गंगा-यमुना का प्रवाह उनकी आत्मा में है और उत्तराखंड जो आदि काल से वैदिक संस्कृति के लिए जाना जाता है, वही उनकी दृष्टि को दिशा देती है। इस के हर सुख-दुख में नरेंद्र मोदी हिंदू हिमालयी राज्य के लोगों के साथ खड़े दिखे, तब भी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने जो भी आपदा झेली, नरेंद्र मोदी सबसे पहले कर संरक्षित हैं। इनमें से एक श्वेत बचाव दल, सामग्री तथा राहत प्रदान की।

वर्ष 2000 में दूरदर्शी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठित यह राज्य पहाड़ी महिलाओं के अभूतपूर्व आंदोलन से गुजरा था। अटल जी ने ठीक ही कहा था कि इस राज्य का जन्म मां की शक्ति से हुआ है। मातृ-शक्ति ने नया राज्य बनाया, जिसमें बड़ी आकांक्षाएं और उम्मीदें थीं। हिमालयी राज्य की महिलाओं के सपनों को साकार करना बाकी है।

कुख्यात मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान कई लोगों ने अपनी काम गंवाई और महिलाओं पर क्रूर अत्याचार हुए। उत्तराखंड राज्य आदि शंकराचार्य ने गंगा व शिव की स्तुति में प्रसिद्ध भजन लिखे तथा अंत में हिमालय के केदारनाथ क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त किया। अलकनंदा और गंगोत्री के संगम पर स्वर्गिक सुंदर देव प्रयाग में गंगा को अपना नाम मिलाता है। शिव-पार्वती की प्रिय भूमि, मां नंदा देवी हमारी पुत्री भी हैं, जिन्हें मां के रूप में पूजा जाता है और हर बारहवें वर्ष 22 दिनों में 280 किमी की भयं नंदा राज यात्रा (मां नंदा की राजकी यात्रा) होती है। गंगा तट पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार महाकुंभ स्थल लाखों तीर्थयात्रियों व योग प्रेमियों को

आकर्षित करते हैं। अविभाजित उत्तराखंड ने दो प्रसिद्ध मुख्यमंत्री दिए— गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी तथा वर्तमान में भी राज्य के मुख्यमंत्री, जो देश को प्रधानमंत्री देने के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड से हैं।

भारत की रक्षा सेनाएं उत्तराखंड के वीर योद्धाओं के विना अधूरी हैं। ब्रिटिश साल में गम्बर सिंह नेगी और दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से लेकर परम वीर चक्र प्राप्त मेजर धन सिंह थापा और अमर किंवदंती राइफलमैन जसवंत सिंह रावत तक, दो को सबसे अधिक सैनिक देने वाले इस राज्य के बहादुर देशभक्त योद्धाओं की लंबी सूची है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से थे और दूसरे जनरल अनिल चौहान भी। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी शीला पीएमओ व वैज्ञानिक संस्थानों में कई उच्च पदाधिकारी इसी राज्य से हैं। इस राज्य ने दुनिया को कि किंवदंती दी हैं, उन्हें नाम देना कठिन, अति संभव नहीं — नवीनतम महिला क्रिकेट सनसनी स्नेह राणा से लेकर प्रथम एवरेस्ट नुनोशी मलिक, अभियुक्त, ऋषभ पंत, रिकिन बॉन्ड, नरेंद्र सिंह नेगी, बसंती बिष्ट यह मां भारत की गौरव और सितारों की अंनंत सूची है। गुंगा तट से योग और आयुर्वेद की धृवों तक ले जाने वाले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले महर्षि महेश योगी, प्रकृति के शाश्वत कवि सुमित्रानंदन पंत से लेकर हिंदू धर्म अस्पष्टता के पुनर्जागरणकर्ता स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद तक, सभी ने इस भूमि से गर्मजोशी और प्रेरणा पाई है। हमारे अपने समय में बाबा नीब करौरी, कैची धाम — स्टीव जॉन्स के गुरु — ने इस हिमालयी राज्य की आभा को बढ़ाया है। देहरादून शहर स्वयं सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक और रक्षा संस्थानों, ज्ञान और विज्ञान के केंद्रों का घर है — ओएनजीसी, नौसेना अनुसंधान संस्थान, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का मुख्यालय यहीं है।

सिलिकॉन सेल: एआई मॉडल बायोमेडिसिन को बदल सकते हैं



विजय गर्ग

दृढ़ औषधि खोज: शोधकर्ता महंगे और समय लेने वाले भौतिक प्रयोगशाला प्रयोगों में शामिल होने से पहले आभासी स्वस्थ और बीमार कोशिकाओं (जैसे कैंसर कोशिकाएं) पर लाखों संभावित दवा यौगिकों के प्रभाव का त्वरित अनुकरण कर सकते हैं। इससे स्क्रीनिंग समय और विकास लागत में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है।

“सिलिकॉन सेल” की अवधारणा परिष्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल के विकास को संदर्भित करती है जो जीवित जैविक कोशिकाओं के कम्प्यूटेशनल प्रतिकृति के रूप में कार्य करते हैं। ये एआई सेल मॉडल शोधकर्ताओं को सिलिकॉन (कंप्यूटर में) में जटिल कोशिका व्यवहार और बातचीत का अनुकरण करने की अनुमति देकर बायोमेडिसिन में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं, जिससे खोज और चिकित्सीय विकास नाटकीय रूप से तेज हो जाता है। सिलिकॉन सेल मॉडल क्या है? सिलिकॉन सेल मॉडल का उद्देश्य वास्तविक कोशिका या उप-प्रणाली का सटीक, तंत्र आधारित डिजिटल प्रतिनिधित्व होना है। सरल बक्क-फिटिंग मॉडलों के विपरीत, ये एआई संचालित प्रतिकृति एंडाइन-अपर हैं, जिनमें प्रोटीन, जीन और चयापचय जैसे सभी आणविक घटकों की प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित गुण और गतिशील पैरामीटर स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं। लक्ष्य केवल डेटा को फिट करने के बजाय सेल की सिस्टम-स्तरीय व्यवहार की सटीक गणना करना है। यदि गणनाकृत व्यवहार प्रयोगात्मक अवलोकनों से मेल नहीं खाता है, तो यह वर्तमान जैविक समझ या मॉडल की संरचना में एक त्रुटि का संकेत देता है, जिससे मॉडल को सृष्टा और परिष्कृत किया जाता है। बायोमेडिसिन में परिवर्तनकारी क्षमता एआई सेल मॉडल बायोमेडिकल अनुसंधान, दवा विकास और व्यक्तिगत चिकित्सा के संचालन को मौलिक रूप से बदलने का वादा करते हैं।

दृढ़ औषधि खोज: शोधकर्ता महंगे और समय लेने वाले भौतिक प्रयोगशाला प्रयोगों में शामिल होने से पहले आभासी स्वस्थ और बीमार कोशिकाओं (जैसे कैंसर कोशिकाएं) पर लाखों संभावित दवा यौगिकों के प्रभाव का त्वरित अनुकरण कर सकते हैं। इससे स्क्रीनिंग समय और विकास लागत में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है।

रोग मॉडलिंग: मॉडल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कैंसर या न्यूरोडेजेनेरेटिव डिस्ऑर्डर जैसी विशिष्ट बीमारी सेल्युलर स्तर पर कैसे आगे बढ़ेगी, जिसमें सिमुलेशन भी शामिल है कि कोशिकाएं उपचार का प्रतिरोध कैसे कर सकती हैं। इससे रोग तंत्र में गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है।

परिशुद्धता और व्यक्तिगत चिकित्सा: रोगी की कोशिकाओं का एक रैडिजिटल जुड़वांर बनाकर, डॉक्टर उस व्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी उपचार निर्धारित करने

सुपरमून क्या है? इसके मूल में, एक सुपरमून तब होता है जब दो चीजें मेल खाती हैं चंद्रमा पूर्ण है (उदाहरण के लिए, पृथ्वी-चंद्र-सूर्य रेखा संरेखित की गई है ताकि चंद्रमा पूरी तरह से उजला हो।) चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। चूंकि चंद्रमा की कक्षा एक परिपूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि एक दीर्घवृत्त है, इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी भिन्न होती है। परिधि पर यह लगभग 363,300 किमी (लगभग 226,000 मील) दूर हो सकता है, सबसे दूर (अपोजी) में लगभग 405,500 किलोमीटर (लगभग 251,000 मील)।

जब उस परिधि के पास पूर्ण चंद्रमा होता है, तो वह थोड़ा बड़ा और उज्वल लगता है - जिसे लोकप्रिय रूप से रसुपरमूनर कहा जाता है।

समूह से कहें तो रसुपरमूनर शब्द कोई आधिकारिक खगोल विज्ञान नाम नहीं है। यह एक लोकप्रिय शब्द है - अधिक औपचारिक शब्द र्पेरिगेयू पूर्ण चंद्रमा या पेरिगे-साइजि।

यह कितना बड़ा या चमकदार है? संख्याएं यह दिखाने में मदद करती हैं कि सुपरमून कितना शानदार है

सुपरमून के पीछे विज्ञान

नासा के अनुसार, वर्ष का सबसे छोटा पूर्ण चंद्रमा (यानी अंतराल पर) की तुलना में सुपरमून लगभग 14% बड़ा दिखाई दे सकता है। यह प्रकाश के मामले में भी लगभग 30% उज्वल लग सकता है जब बाकी सब कुछ बराबर होता है। हालांकि, व्यावहारिक देखने की परिस्थितियों में (वृक्षों और इमारतों आदि के साथ आपकी रात का आकाश) अंतर अक्सर सूक्ष्म होता है और नग्न आंख से आसानी से दिखाई नहीं दे सकता। तो हाँ - यह मांसन योय रूप से बड़ा और उज्वल है। लेकिन एक ऐसा चंद्रमा की उम्मीद मत करो जो दो बार बड़ा या अंधाधुंध रूप से विशाल दिखाता हो।

ऐसा क्यों होता है: कक्षा यांत्रिकी आइए चरणों को तोड़ दें एलिप्टिकल कक्षा - पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष थोड़ा दीर्घवृत्त होता है, जिसका अर्थ है कि ऐसे समय होते हैं जब यह करीब और दूर हो जाता है। सिंजिगी (संरेखण) - जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के विपरीत चंद्रमा से संरेखित होते हैं तो पूर्ण चंद्रमा होता है (इस प्रकार पृथ्वी का सामना करने वाली पक्ष पूरी तरह से प्रकाशित होती है।) पेरिगे + पूर्ण चरण - जब पूर्ण चरण पर या उसके बहुत करीब होता है, तो आपको सुपरमून मिलता है। दृश्य प्रभाव - चूंकि चंद्रमा करीब है, इसलिए इसका कोण आकार (यह हमारे आकाश में दिखाई देता है) थोड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा, निकट होने का मतलब यह प्रकाश थोड़ा अधिक तीव्रता से हमारे पास पहुंच जाता है, इसलिए यह थोड़ा चमकदार लगता है। चंद्रमा का भ्रम - यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा क्षितिज पर

बहुत बड़ा दिखाता है र मनोवैज्ञानिक/ऑप्टिकल प्रभाव, जो अक्सर हमारे लिए कितना बड़ा लगता है। लेकिन यह प्रभाव सुपरमून से अलग है। आप क्या देखेंगे और कब देखेंगे है एक सुपरमून देखने का सबसे अच्छा समय चंद्रमा के उतारने (या सूर्यास्त से ठीक पहले) है जब चांद आकाश में कम होता है। क्षितिज स्थलों के बगल में यह विशेष रूप से बड़ा लग सकता है। आपको दूरबीन की आवश्यकता नहीं है: यह नग्न आंखों से दिखाई देता है। लेकिन रसायान्द्र पूर्ण चंद्रमा की तुलना में आकार/उज्वलता अंतर को अलग करने के लिए साइड-बाय छवि या संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि ये वर्ष में केवल कुछ बार होता है (आमतौर पर 3 से 4 बार) समय ऐसा है जिसके लिए स्काईवाचर्स योजना बना सकते हैं। पृथ्वी और मिथकों पर प्रभाव लहरें और गुरुत्वाकर्षण:

चूंकि चंद्रमा थोड़ा करीब है, इसकी गुरुत्वाकर्षण कुछ हद तक मजबूत होता है। इससे तटीय क्षेत्रों में थोड़ा अधिक उच्च तरंगें (पेरिगेन वसंत तरंगें) या थोड़ी कम कम तरंगें हो सकती हैं। लेकिन अंतर छोटा है (सेंटीमीटर के क्रम में) और अकेले ही बड़ी तरंगें आपादाएं पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपदाओं के बारे में मिथक:

कुछ लोकप्रिय मीडिया ने सुझाव दिया है कि सुपरमून भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जांच में सुपरमून चंद्रमा और टेक्टोनिक गतिविधि के बीच कोई सुसंगत संबंध नहीं दिखाया गया है। जैसा कि

एन की सुरक्षा' अहम भूमिका निभाती है। रोजाना सात से आठ घंटे की नींद लेना डीएनए की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली को सक्रिय रखता है। योग, ध्यान और हल्का व्यायाम तनाव को नियंत्रित करते हैं तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे टहलना, दौड़ना या साइकिल चलाना, कोशिकाओं को पर्याप्त आक्सीजन पहुंचाती हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखती हैं। टीकाकरण कुछ बीमारियों से बचाव का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। एचपीवी और हेपेटाइटिस-बी के टीके से कैंसर के खतरों को कम करने का दावा किया गया है। इसके अलावा, दोपहर की तेज धूप से यथासंभव दूरी बनाए रखना बेहतर उपाय है। डीएनए की सुरक्षा की दृष्टि से धूम्रपान और शराब से परहेज करना भी महत्वपूर्ण उपायों में शामिल है।

दुनिया भर भर में वैज्ञानिक ज्ञानिक डीएनए की सुरक्षा और उतार के लिए मरम्मत के लिए निरंतर नए उपायों पर कार्य कर रहे हैं। मगर जब तक ये खोजें आम जीवन का हिस्सा नहीं बनतीं, साधारण लोगों तक उनकी तब तक हमें अपनी जीवनशैली, आदतों ठीक उनकी पहुंच नहीं होती, परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन लाकर स्वयं अपने डीएनए की सुरक्षा करने के लिए सतर्क रहना होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा डीएनए में ही दर्ज है। यदि यह सुरक्षित और संतुलित है, हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य भी सुखद, सुदृढ़ और स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें इन अदृश्य हमलों के प्रति अब व्यापक रूप से जागरूक होने की जरूरत है और अपने डीएनए की सुरक्षा को जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना होगा, क्योंकि सुरक्षित डीएनए ही एक सुरक्षित जीवन की नींव है, जिसका मजबूत बने रहना बेहद जरूरी है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सेवानिवृत्

11 नवंबर: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विशेष शिक्षा भविष्य की बुनियाद लेकिन हिल रही नींव

राजेश जैन

हमारे बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं और शिक्षा उन्हें दिशा देती है। दूसरी ओर स्कूल और कॉलेज में सीखने-सीखने का उद्देश्य कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस की क्रांति के दौर में है, तब भी हमारा शिक्षण मॉडल 20वीं सदी की जरूरतों पर टिका हुआ है। यही कारण है कि हम 'ज्ञानवान भारत' का सपना देखते हुए भी 'नौकरी ढूँढते भारत' में बदल गए हैं। आइए, शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों को गहराई से समझते हैं और साथ ही देखते हैं कि उनसे निपटने के रास्ते क्या हो सकते हैं।

सरकार की प्राथमिकता में नहीं है शिक्षा
सरकारी वादे के मुताबिक शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए था, पर हकीकत में यह 3% के आसपास ही सिमटा है। इतना ही नहीं, शिक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और प्रशासनिक खर्चों में चला जाता है, जबकि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाओं, डिजिटल उपकरणों या शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम खर्च होता है। इससे प्रामाण्य स्कूलों में बच्चों के पास न बचे हैं, न लैब। विश्वविद्यालयों में शोध के लिए उपकरणों की कमी है। इससे निपटने के लिए शिक्षा को खर्च नहीं, निवेश माना जाए। केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा बजट में क्रमिक बढ़ावों का दीर्घकालिक रोडमैप बनाना चाहिए।

बच्चों को सिखा रहे बने जमाने की बातें
देश के अधिकांश स्कूलों और विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम दशकों पुराना है। आज भी कई किताबों में वही उदाहरण हैं जो हमारे दादा-पिता के जमाने में थे। नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण परिवर्तन, साइबर सुरक्षा या डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषय अब भी "अतिरिक्त पठन सामग्री" माने जाते हैं। इससे हमारे बच्चे परीक्षा पास करने लायक तो बनते हैं, पर जीवन और काम की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। इससे पार पाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हर 3-5 साल में पाठ्यक्रम की समीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम अपडेट करने की प्रक्रिया में उद्योग जगत, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय कक्षा 6 से ही लागू किए जाएं।

अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग-अलग शिक्षा
आज शिक्षा भी वर्गों में बंट गई है। एक तरफ स्मार्ट क्लासरूम, रोबोटिक्स और इंटरनेशनल बोर्ड हैं, तो दूसरी तरफ ब्लैकबोर्ड तक नहीं। यह असमानता ही सामाजिक असमानता में बदलती है। इससे निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार पर फोकस किया जाए। सीएसआर फंड और 'एडॉप्ट-ए-स्कूल' अभियान को मजबूत बनाया जाए। डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए हर गांव में कॉमन डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाने की जरूरत है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव
हमारे स्कूलों में विज्ञान तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच नहीं सिखाई जाती। नतीजतन, समाज में अंधविश्वास, भ्रांतियां और छद्मविज्ञान की जड़ें गहरी हो रही हैं। आज भी लोग इलाज की बजाय ताबीज ढूँढते हैं, और सोशल मीडिया पर फैलने वाले अफवाहों को बिना जांचे मान लेते हैं। इससे निपटने के लिए हर स्तर



पर सार्इटिफिक टेम्प्लामेंट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। बच्चों में तर्कशीलता, प्रश्न पूछने और प्रमाण खोजने की आदत डाली जाए। साइंस फेस्टिवल, इन्वेंशन फेयर और विज्ञान जैसे कार्यक्रमों को सामाजिक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है।

रत्ने की परंपरा से रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की कमी
हमारा सिलेबस और परीक्षा दोनों ही सही जवाब खोजने पर केंद्रित हैं, सही जवाब पूछने पर नहीं। शिक्षा व्यवस्था अंक-केंद्रित है। इससे बच्चे 100 में 100 लाने के लिए रतते हैं। सोचने की प्रक्रिया हिल रही है। ऐसे में जब वास्तविक जीवन में समस्या आती है, तो वे हिल निकालने में असाहय दिखते हैं। यही कारण है कि देश में इन्वेंशन और पेटेंट की दर कम है। इससे निपटने के लिए शिक्षण पद्धति को इंक्वायरी-बेस्ड और एक्टिव लर्निंग मॉडल पर आधारित करना होगा।

फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से सीख लेकर प्रोजेक्ट-बेस्ड शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। स्कूलों में थिंकिंग लैब्स शुरू की जा सकती हैं, जहां बच्चे वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजें। कला, संगीत, डिजाइन और इन्वेंशन को मुख्य धारा में लाया जाए। परीक्षाओं में रचना-आधारित सवालों की जगह ओपन-एंडेड प्रश्न शामिल हों। 'इन्वेंशन फेस्टिवल' जैसी योजनाओं से बच्चों को प्रयोग करने की आजादी मिले।

शिक्षकों का सम्मान और प्रशिक्षण की कमी
भारत में शिक्षक 'गुरु' कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार में उनका सम्मान घटता जा रहा है। प्रशासनिक दबाव, रिजल्ट का बोझ और सीमित संसाधन उन्हें थका चुके हैं। कई जगहों पर शिक्षक खुद नई तकनीकी से अनजान हैं। ऐसे में हर शिक्षक को साल में कम से कम दो बार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने की जरूरत है।

नेशनल टीचर फेलोशिप प्रोग्राम जैसी पहल से उन्हें रिसर्च और ट्रेनिंग का अवसर दिया जाए। मीडिया और समाज को भी शिक्षक के योगदान को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

डिग्री है, दिशानहीं
आज लाखों युवाओं के पास डिग्रियां हैं, लेकिन रोजगार नहीं। क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई अर्थव्यवस्था की जरूरतों से मेल नहीं खाती। दुनिया डेटा साइंस, एआई और साइबर सिस्टिमीटी की बात कर रही है, जबकि हमारे कॉलेज अब भी एम्प्लॉयमेंट और एग्सेल सिखाने में लगे हैं। जरूरत है कि सेवा और उद्योग जगत के साथ कोर्स को-डेवलपमेंट की व्यवस्था बने।

असम का विधान, नारी सम्मान का नया संविधान [असम से उठी वह लहर, जो समाज की दिशा बदल देगी]



एक छोटा-सा राज्य, एक विराट फैसला। असम की मिट्टी में सदियों से जड़ जमाए बहुविवाह की प्रथा अब कानून की मजबूत दीवार से टकराने वाली है। रविवार की उस शांत शाम, जब गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी लहरों को समेटे चुपचाप बह रही थी, उसी क्षण मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने एक ऐसा बिल पारित किया जिसने पूरे पूर्वोत्तर को स्तब्ध कर दिया— 'असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025'। 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होने वाला यह कानून न केवल एक व्यक्ति को एक से अधिक जीवित पत्नी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा, बल्कि उल्लंघन करने वालों को सात वर्ष तक की कठोर कैद और पीडित महिलाओं को न्यायचित मुआवजे का मजबूत अधिकार भी देगा। यह कोई साधारण विधेयक नहीं; यह एक सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष है— जहाँ एक ओर महिलाओं की गरिमा का प्रश्न है, तो दूसरी ओर सदियों पुरानी परंपराओं का अटूट किला।

सबसे पहले समझना जरूरी है कि बहुविवाह असम में कोई दुर्लभ प्रथा नहीं रही। खासकर कुछ समुदायों में इसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। जमीन-जायदाद विवरणों से बचाने के नाम पर, वंश-वृद्धि के नाम पर, या बस इसलिए कि 'हमारे पूर्वजों की यही रीति थी'— बंधाने अनगिनत थे। किंतु इन बंधानों के पीछे छिपी थीं हजारों महिलाओं की कुचली हुई आंकांक्षाएँ, टूटे हुए सपने। दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी बनकर घर में प्रवेश करने वाली स्त्री न कानूनी अधिकार रखती थी, न सम्मान। बच्चे जन्म लेते थे, पर उनका भविष्य हमेशा अनिश्चय के अंधेरे में लटका रहता था। संपत्ति का हक? वह तो पहली पत्नी के बच्चों को ही दुलभ था। सरकार ने ठीक यही प्रहार किया है— उस जड़ पर, जो सदियों से महिलाओं को रौंदती आई है।

कानून का मौसदा स्पष्ट है— कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म या समुदाय का हो, एक जीवित पत्नी रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। अपवाद सिर्फ उन मामलों में है जहाँ पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो या तलाक हो चुका हो। उल्लंघन पर सात वर्ष की सजा और जुर्माना। पर सबसे क्रांतिकारी है मुआवजे का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति छिपाकर दूसरा विवाह करता है, तो पीडित पत्नी को न्यायालय के माध्यम से मुआवजा मिलेगा। यह प्रावधान इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक ऐसी महिलाएँ न पुलिस के पास जाती थीं, न अदालत में। शर्म, सामाजिक दबाव और आर्थिक मजबूरी उन्हें मौन रहने को बाध्य करती थी। अब कानून उन्हें सशक्त आवाज दे रहा है।

विरोध अपेक्षित था। बिल की खबर जैसे ही बाहर आई, कुछ संगठनों ने इसे 'सांस्कृतिक आक्रमण' करार दिया। उनका दावा है कि यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है, क्योंकि इस्लाम में चार विवाहों की अनुमति है। किंतु सरकार का उत्तर अडिग है— यह बिल किसी धर्म-विशेष के विरुद्ध नहीं। हिंदू, ईसाई, आदिवासी— सब पर समान रूप से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, "हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे; हम केवल महिलाओं को उनका जन्मसिद्ध अधिकार लौटा रहे हैं।" वास्तव में यह यूनियनर्स मिलिटल कोड की दिशा में असम का पहला दृढ़ कदम है। केरल, गोवा जैसे राज्य पहले से इस पथ पर हैं। असम अब गर्व से उस सूची में शामिल हो रहा है।

दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता इसे युगांतकारी बता रहे हैं। गुवाहाटी की एक वकील कहती हैं, "मैंने सैकड़ों महिलाएँ देखां जो दूसरी-तीसरी पत्नी बनकर नौकरानी से बदतर जीवन जीती हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पिता उनका नाम तक नहीं लिखाता। यह बिल उन्हें न्याय की किरण देगा।"

कानून का मौसदा स्पष्ट है— कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म या समुदाय का हो, एक जीवित

तोता है जब हम किसी को चाहे, बिना उसे अपने होने की शर्त पर बाँधें। यह पीड़ा हमें निर्मल बनाती है। जो भीतर से टूटा है, वही करुणा को वास्तविक रूप में समझ सकता है। यह टूटन ही हमें दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता देती है। इसीलिए, अपनों

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

एक महिला शिक्षक की मौन कहानी

हर सुबह, मैं अपने ही बच्चे को घर पर छोड़ जाती हूँ, किसी और के बच्चे को सिखाने जाती हूँ।

मैं कहती हूँ—
"टिफिन खाओ, पानी पीना मत भूलना, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो"
और उसी पल सोचती हूँ—
क्या मेरा अपना बच्चा भी खाना खा पाया होगा?

मैं घंटों बच्चों के सपनों को आकार देती हूँ, जबकि मेरा नन्हा-सा अपने सोने की कहानी के लिए माँ का इंतजार करता है।

मैं सिर्फ अक्षर नहीं सिखाती, मैं अक्षरों से भविष्य लिखती हूँ।
मैं स्कूल में बच्चों के आँसू पोंछती हूँ, और मेरा बच्चा शायद घर में चुपचाप रो रहा होता है।

और जब दुनिया पूछती है—
"तुम ये सब क्यों करती हो?"
मैं मुस्कुरा देती हूँ।

क्योंकि शिक्षक होना मतलब है हजारों बच्चों का भार उठाना, उनके भविष्य को गढ़ना, भले ही अपने मन की शांति तोड़नी पड़े उस बच्चे के लिए जिसे मैंने जन्म दिया था।



मुस्कुरा रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी : (आलेख : संजय पराते)

न्यूयॉर्क बंदरगाह के सामने खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ट्रुपियन अमेरिका की हार की घोषणा कर रही है। न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत मोदीवाइत हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने पर आमादा। दोनों चोर कम्युनिस्ट विरोधी और मुस्लिम विरोधी। दोनों अपने देश के लोकतांत्रिक स्वरूप और उदात्त पूंजीवादी मूल्यों को खत्म करके 'निर्वाचित तायाशाही' लादने और नागरिकों को 'आज्ञापालक प्रजा' में बदलने पर आमादा। लेकिन दोनों को अपने देश की जनता से चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में ममदानी, जो अपने-आपको वामपंथी कहते हैं, जो जन्म से मुस्लिम हैं— और जिसे अमेरिकी नागरिकता मिले मुश्किल से 7 साल ही हुए हैं, यदि जनता द्वारा अपार बहुमत से चुने जाते हैं, और चुने जाने के बाद अपने पहले ही भाषण में जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत

करते हैं, तो दोनों का सन्निपात की अवस्था में पहुंचना तय था। ममदानी का जीतना इस बात का ऐलान है कि अब अमेरिकी जनता ट्रंप की नीतियों के खिलाफ निर्णायक ढंग से खड़ी हो रही है, ठीक उसी प्रकार, जैसे भारत में लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूर्ण बहुमत की स्थिति को खोना और दो बैसाखियों के सहारे सरकार बनाना, इस बात का ऐलान है कि भारतीय नागरिक भाजपा-आरएसएस और मोदी की नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।

दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भारतवंशी जीतता है, तो भाजपाई खेमा और संघी गिरोह 'भारतमाता की जय' की पुकार लगाते हुए उछलकूद करने लगता है। ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर हमने ऐसा ही देखा था। वास्तव में ऐसी जीत का भारत से कोई संबंध नहीं होता था और न भारत को कोई फायदा, लेकिन यह बंदर-कूद इसलिए होती है कि भारतवंशी के नाम पर यहाँ राष्ट्रवादी उन्माद भड़काया जा सके। लेकिन ममदानी की जीत से भाजपा को फायदा उठाने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि ममदानी का इतिहास नस्लवादी राष्ट्रवाद के खिलाफ तनकर खड़े होने और गरीबी और असाहय लोगों के पक्ष में संघर्ष करने का इतिहास रहा है। ये ममदानी ही थे, जिन्होंने अमेरिका के आवास संकट को उसके असली स्वरूप में पहचाना और समझा कि इस संकट की असली जड़ कॉर्पोरेट मुनाफे की हवस और अश्वेतों के खिलाफ नस्लवादी मानसिकता है। न्यूयॉर्क का मेयर बनने से पहले वे न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा से विधायक थे और एक विधायक के रूप

में जनता के लिए उन्होंने ये संघर्ष किया है। ये ममदानी ही थे, जिन्होंने हेड्सली चालकों के साथ उनकी 45 हफ्ता में शामिल होकर उन्हें 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋणा रहत दिलाई थी। ये ममदानी ही थे, जिनके संघर्ष के कारण न्यूयॉर्क राज्य को मेट्रो सेवा में वृद्धि और किराया-मुक्त बस व्यवस्था के लिए राज्य के बजट में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का प्रावधान करना पड़ा था। ये ममदानी ही थे, जिन्होंने आम जनता के संगठित करके न्यूयॉर्क में प्रस्तावित एक प्रदूषणकारी बिजली संयंत्र को रोकने में सफलता हासिल की थी। इन संघर्षों ने कॉर्पोरेट मुनाफे को सीधी चोट पहुंचाई है। ऐसे ममदानी से ट्रंप और मोदी, दोनों का हाजमा खराब ही होना था।

निकट अतीत में डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं था, जो उनके जैसे संघर्षों की आग में तपा हो। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वामपंथी की धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने दक्षिणपंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी प्राप्त की। बाद में कुओमो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव के लिए खड़े हुए। ये ममदानी ही थे, जिन्होंने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खुलकर फिलिपसिनी मुक्ति संघर्ष का समर्थन किया है, जिसके कारण ट्रंप ने उन पर यहूदीविरोधी होने का

आरोप लगाते हुए उन्हें हराने की खुली अपील की और कुओमो को अपना समर्थन दिया। लेकिन कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा, दोनों को हराकर, न्यूयॉर्क की आधी से ज्यादा जनता का समर्थन प्राप्त करके ममदानी निर्वाचित हुए। इसलिए ममदानी की जीत ट्रंप की इजरायलपरस्ती की भी हार है।

ममदानी का चुनाव अभियान और उसकी मांगें उनके संघर्षों से निकली थीं। उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों को स्थिर किया पर आवास उपलब्ध कराने, विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनाने, बच्चों की देखभाल की निःशुल्क व्यवस्था करने और महंगाई से राहत देने के लिए सस्ती कीमतों वाली दुकानों का संचालन करने जैसी मांगों पर अभियान चलाया। ये मांगें एक कल्याणकारी राज्य के तनुकूल हैं, लेकिन नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि ये नीतियां जनकल्याण के बजाए मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जनकल्याण बनाम कॉर्पोरेट मुनाफे का संघर्ष बहुत तेज हो गया है। ममदानी की जीत इसी संघर्ष की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि ममदानी की जीत से खफा ट्रंप अब न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देने की धमकी दे रहे हैं, तो ममदानी ने भी साफ विकल्प रखा है कि जन कल्याण के कार्यों के लिए राशि जुटाने के लिए वे अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे। साफ है कि जब



लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

लगत है कि प्रेम, स्वामित्व नहीं है, वह एक अर्पण है, और हर अर्पण में हानि की संभावना निहित होती है। अपनों का दर्द हमें सिखाता है कि स्नेह में अधिकार जितना अधिक हो, उतनी ही गहरी चोट उसका अभाव देता है। इसलिए सच्चा प्रेम तब जन्म

का दिया गया दर्द अंत नहीं, आरंभ है। आत्म-साक्षात्कार का आरंभ। यह हमारे अस्तित्व से झूठ के आवरण हटाकर सत्य का परिचय कराता है, जहाँ हम समझते हैं कि प्रेम में पीड़ा उसका विरोध नहीं, उसका प्रमाण है।

पुराने से नए युग में कदम रख लिया है।" मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणापत्र की पहली पंक्ति है -- रयूरोप को एक भूत सता रहा है -- कम्युनिज्म का भूत है। इस भूत का डर अब विश्वव्यापी हो गया है। कभी यह च ग्वारा के रूप में सामने आता है, कभी जोहरान ममदानी के रूप में। जोहरान ममदानी हो या कोई और, यदि वह

पुराने से नए युग में कदम रखने के घोषणा करता है, तो ऐसे विश्व-नागरिकों से ट्रंप और मोदी दोनों खतरा ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन ममदानी की जीत से पूरी दुनिया के लोगों को होसला मिल रहा है, जो एक न्यायपूर्ण, समानता और अवसरों से भरी दुनिया के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा मुस्कुरा रही है। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ पर एम्मा लाजारस की एक कविता उकेरी गई है : रद न्यूयॉर्क कोलोसस है। यह कविता इन प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ समाप्त होती है : रमुझे अपने थके हुए, अपने गरीब / अपनी तरसती, सिक्की हुई जनता को / अपने भीड़ भरे तट के दयनीय लोगों को / आजाद सांस लेने के लिए दे दो। / इन बेधरों, तुफान से थिरे लोगों को मेरे पास भेज दो / मैं सुनकर देखाऊँ के पीछे अपना दिया उठाती हूँ।

ममदानी की जीत ने आने वाले दिनों में ट्रम्पवाद के खिलाफ संघर्षों का दीया जला दिया है, सुनकर दरवाजे के कपाट खुल गए हैं।

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

